

एक थी तृणमूल!

नाम और चुनाव चिह्न संकट में



नई दिल्ली, 17 सितंबर (एजेंसियां)। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक नियंत्रण और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद अब चुनाव आयोग के सामने पहुंच गया है। आयोग के समक्ष तृणमूल कांग्रेस के दो प्रतिद्वंद्वी गुट आमने-सामने हैं। एक गुट का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, जबकि दूसरे खेमे से रीतब्रत बनर्जी सहित बागी नेता जुड़े हैं। दोनों पक्ष पार्टी और उसके संगठन पर अपना दावा कर रहे हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार आयोग ने उपचुनावों को देखते हुए दोनों पक्षों के दावों और पार्टी के नाम तथा चुनाव चिह्न के इस्तेमाल से जुड़े मामले पर सुनवाई की है।

उपचुनावों के कारण बड़ी आयोग की चिंता
चुनाव आयोग के समक्ष विवाद का केंद्र तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे, अधिकृत

पदाधिकारियों और पार्टी के चुनाव चिह्न पर दोनों पक्षों के दावे हैं। आयोग ने दोनों पक्षों से पार्टी के संगठन और अधिकृत प्रतिनिधियों से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों को देखते हुए इस मामले पर आयोग का फैसला महत्वपूर्ण हो गया है।

पार्टी के भीतर विवाद कैसे शुरू हुआ?
पार्टी के भीतर बगावत का मामला उस समय चुनाव आयोग तक पहुंचा, जब रीतब्रत बनर्जी ने आयोग के समक्ष अपनी याचिका रखी। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति का कार्यकाल 11 फरवरी 2025 को ही समाप्त हो चुका था। इसके बाद उस कार्यसमिति के पास फैसले लेने का कानूनी अधिकार नहीं बचा था। रीतब्रत बनर्जी के पक्ष का कहना है कि 22 जून 2026 को पार्टी का एक विशेष अधिवेशन बुलाया

गया था। इस अधिवेशन में अरूप रॉय को राष्ट्रीय कार्यसमिति का नया अध्यक्ष चुना गया। दूसरी ओर, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले खेमे ने इन दावों को खारिज किया है। ममता गुट के प्रतिनिधियों ने आयोग के सामने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और संबंधित बैठकों की वैधता को लेकर अपना पक्ष रखा है। दोनों पक्षों ने अपने-अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज भी आयोग को सौंपे हैं।

ममता गुट ने दावों को बताया असंवैधानिक
ममता बनर्जी के खेमे ने रीतब्रत बनर्जी और अरूप रॉय से जुड़े दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके द्वारा आयोजित बैठक पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं थी। ममता गुट के कानूनी सलाहकारों और प्रतिनिधियों ने आयोग से कहा कि उक्त बैठक में लिए गए फैसले और नियुक्तियां पार्टी के संविधान के खिलाफ हैं। ममता गुट ने आयोग से बागी नेताओं की ओर से किए गए दावों और भेजे गए पत्रों को स्वीकार नहीं करने की मांग की।

17 सितंबर को दोनों पक्षों को आयोग ने बुलाया
दोनों पक्षों के बीच तिखे दावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 17 सितंबर को नई दिल्ली में दोनों प्रतिनिधिमंडलों को सुनवाई के लिए बुलाया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार रीतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले खेमे को दोपहर 3 बजे और ममता बनर्जी के प्रतिनिधिमंडल को शाम 4 बजे आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। दोनों पक्षों ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, अधिकृत पदाधिकारियों और चुनाव चिह्न पर अपने-अपने दावे पेश किए। ▶**8पर**

बीआरएस पर हमलावर रूख से हलचल बंडी-रेवंत जोड़ी!



ओमप्रकाश सिर
हैदराबाद। 17 सितंबर
तेलंगाना की राजनीति में इन दिनों भाजपा नेता बंडी संजय कुमार के राजनीतिक रूख को लेकर नई बहस छिड़ गई है। भाजपा हाईकमान जहां राज्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ संघर्ष को लगातार राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, वहीं बंडी संजय की हालिया गतिविधियों को लेकर विपक्ष और राजनीतिक हलकों में सवाल उठाए जा रहे हैं। चर्चा का केंद्र यह है कि बंडी संजय कांग्रेस सरकार पर सीधे हमले करने की तुलना में बीआर-

एस और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के परिवार से जुड़े मामलों को अधिक प्रमुखता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा केसीआर से संबंधित जमीन और संपत्तियों की जांच का मुद्दा उठाए जाने के बाद बंडी संजय ने भी बीआरएस नेताओं की कथित जमीनों के खिलाफ 'दंडयात्रा' की घोषणा की। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक बहस को और हवा दी है।

भाजपा के भीतर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ शुल्क प्रतिपूर्ति, सरकारी नीतियों और कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे विधानसभा तथा सार्वजनिक मंचों पर उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में कुछ भाजपा नेताओं की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि राज्य सरकार के खिलाफ पार्टी के आंदोलन को जिस आक्रामकता की जरूरत है, वह बंडी संजय के रूख में क्यों दिखाई नहीं दे रही है।

इसी बीच विपक्षी नेताओं ने बंडी संजय पर आरोप लगाया है कि वे बीआरएस के खिलाफ तो लगातार मुखर हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार की कथित विफलताओं पर अपेक्षाकृत शांत दिखाई देते हैं। हालांकि, यह राजनीतिक आरोप है और बंडी संजय का पक्ष या भाजपा की आधिकारिक रणनीति को अलग से देखा जाना आवश्यक है।

राजनीतिक गलियारों में बंडी संजय और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच ▶**8पर**

‘सिलेंडर महिला’ भारी अब 12 लाख मुआवजा देगा इंडियन ऑयल

नई दिल्ली, 17 सितंबर (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) को एक योग्य महिला उम्मीदवार सुमित्रा को 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आईओसी ने उन्हें केवल महिला होने के आधार पर एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में रीफिलिंग हेल्पर की नौकरी देने से इनकार कर दिया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यह कहकर नौकरी देने से इनकार किया था कि 'महिला सिलेंडर नहीं उठा पाएगी।' सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच की कड़ी आलोचना करते हुए सवाल किया कि क्या महिलाएं एलपीजी सिलेंडर नहीं उठा सकतीं? अदालत ने केवल महिला होने के आधार पर नौकरी से वंचित किए जाने को नारीत्व का अपमान बताया। महिला अब सेवानिवृत्ति की उम्र तक पहुंच चुकी हैं। इसलिए अदालत ने उन्हें नौकरी देने के बजाय 12 लाख रुपये का मुआवजा देना उचित समझा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कॉर्पोरेशन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि केवल महिला होने के आधार पर नौकरी न देना नारीत्व का अपमान है।

इंडियन ऑयल के वकील ने दलील दी थी कि इस काम में भारी एलपीजी सिलेंडर उठाने पड़ते हैं और रात की पाली में भी काम करना होता है। इसलिए संभवतः अधिकारियों ने महिला को इस काम के लिए उपयुक्त नहीं माना। ▶**8पर**

यूपीआई कस्टमर फ्रेंडली दुकानदारों पर होगी कड़ी निगरानी

नई दिल्ली, 17 सितंबर (एजेंसियां)। यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाए जाने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार अब यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआई भुगतान पर लगने वाले 0.4 प्रतिशत मंचेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का बोझ ग्राहकों पर न डाला जाए। नया शुल्क ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। यह शुल्क सीधे ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा, बल्कि संबंधित व्यापारी से वसूला जाएगा। कारोबारियों की ओर से बुधवार को यह बात सामने आई थी कि शुल्क का भार वे अपने ग्राहकों पर डाल सकते हैं। इसके बाद सरकार ने इस मामले पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है कि ग्राहक से यूपीआई भुगतान के नाम पर अलग से शुल्क न वसूला जाए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने भी स्पष्ट किया है कि एमडीआर को ग्राहकों पर नहीं डाला जा सकता।

15 अक्टूबर से लेन-देन की दैनिक निगरानी
सरकार के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार, शुल्क का भार ग्राहकों पर पड़ने से रोकने के लिए कारोबारियों और भुगतान एग्रीगेटरों के बीच आवश्यक व्यवस्था को लेकर बातचीत चल रही है। सरकार इस मामले में कारोबारियों और भुगतान एग्रीगेटरों के संपर्क में है। 15 अक्टूबर के बाद यूपीआई भुगतानों की रोजाना निगरानी की जाएगी ▶**8पर**

उद्धव-ममता के साथ मोर्चा



ओर से बताया गया कि बैठक में परिसीमन के मुद्दे, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन की स्थिति और विपक्ष में क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर चर्चा हुई।यह मुलाकात ऐसे समय हुई, जब तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में तनाव की चर्चा है। कांग्रेस ने अभिनेता विजय की पार्टी तमिलनाडु वेत्ती कड़गम के साथ राजनीतिक तालमेल बढ़ाया है। इसके बाद डीएमके और कांग्रेस के बीच दूरी को लेकर अटकलें तेज हुई हैं। कनिमोड़ी ने इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी एवं लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले से भी मुलाकात की। इन बैठकों में भी क्षेत्रीय दलों के बीच समन्वय और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने

की बात सामने आई है।

तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश नई नहीं
गौरतलब है कि कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश भारतीय राजनीति में पहले भी कई बार हो चुकी है। 2013 में ममता बनर्जी ने गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा दलों को साथ लाकर 'संघीय मोर्चा' की बात उठाई थी। इसके कुछ साल बाद तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया। उन्होंने ममता बनर्जी और नवीन पटनायक समेत कई क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यह प्रयास आगे नहीं बढ़ सका।2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ लाकर 'प्रगतिशील राज्यों का समूह' बनाने की पहल की थी। हालांकि, यह विचार भी किसी व्यापक राष्ट्रीय मोर्चे में तब्दील नहीं हो पाया।

ममता से मुलाकात पर टिकी नजरे
कनिमोड़ी की प्रस्तावित ममता बनर्जी से मुलाकात को इसी व्यापक राजनीतिक संपर्क अभियान के क्रम में देखा जा रहा है। हालांकि, दोनों नेताओं की मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि और उसके एजेंडे को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में इसे फिलहाल क्षेत्रीय दलों के बीच संवाद और समन्वय की कवायद के रूप में ही देखा जा रहा है। ▶**8पर**

जन्म-मृत्यु हाथों-हाथ पंजीकरण में देरी की तो खैर नहीं

नई दिल्ली, 17 सितंबर (एजेंसियां)। देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और समयबद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कानूनी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के सभी प्रावधान आगामी 1 अक्टूबर 2026 से देशभर में लागू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से 16 सितंबर को जारी राजपत्र अधिसूचना में इसकी पुष्टि की गई है। संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में यह नया संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु की घटनाओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा देर से होने वाले पंजीकरण में सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाना है।

एक से दो साल की देरी पर अधिकारी की मंजूरी जरूरी
नए संशोधन के तहत यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका पंजीकरण संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित अधिकारी को जन्म या मृत्यु की घटना की सत्यता की जांच करनी होगी और निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होगा। ▶**8पर**

बांसवाड़ा, 17
सितंबर (शुभ लाभ
ब्यूरो)। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का
जन्मदिन के अवसर
पर गुरुवार को
नसुरुल्लाबाद मंडल
केंद्र में सेवा कार्यक्रम
गाड़ी केंद्र के बच्चों को
हनमंडलू ने प्रधानमंत्री
तत्व में देश विकास के
ह्ममान बढ़ा है। उन्होंने
मना की। कार्यक्रम में
सतीश, गंगाधर गुप्ता,
ने मोर्चा मंडल अेलक्ष
पल्ली श्रीनू, जेला सैलू,

उन्नी वंशज मुक्ताबाई निवृत्ति सावते का सम्मान किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार डॉ. शारदा चौडेकर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी चंद्रशेखर कदम, पुलिस निरीक्षक जगदीश मंडलवार सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, नगर परिषद एवं कांग्रेस कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया।

गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र और देवी सरस्वती हैं। यदि शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार इसका जाप किया जाए, तो मां सरस्वती प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है...

वेदमाता गायत्री

गायत्री शब्द का अर्थ है प्राणरक्षक। 'गाय' कहते हैं प्रण को तथा 'त्री' का तात्पर्य है त्राण संरक्षण करने वाली। अतः जिस शक्ति से प्राण का, प्रतिभा का व जीवन का संरक्षण होता है, उसे गायत्री कहते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से गायत्री के चार भागों का व्याख्यान चार वेदों के रूप में किया था। इसी कारण गायत्री को वेद माता कहते हैं। यह गायत्री मंत्र भारतीय संस्कृति, धर्म एवं तत्वज्ञात का बीज है।

त्रियदा गायत्री

गायत्री वैदिक संस्कृत का एक छंद है, जिसमें आठ-आठ अक्षरों के तीन चरण कुल 24 अक्षर होते हैं। 'ॐ भूर्भुवः स्वः' यह गायत्री का शीर्ष कहलाता है। शेष आठ- आठ अक्षरों के तीन चरण हैं। इन्हीं तीन चरणों के कारण गायत्री को त्रियदा कहा जाता है। एक शीर्ष तथा तीन अन्य चरण इस प्रकार उसके चार भाग बने। इन चारों चरणों का रहस्य ही वेदों में वर्णित किया गया है।

मंत्र का भानार्थ

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्य भगो



देवस्य धीमहि। धियो योनः प्रचोदयात्

प्रत्येक वेदमंत्र के प्रारंभ में ॐ का प्रयोग किया जाता है। ॐ कार ईश्वर का द्योतक है। गायत्री मंत्र में भी ॐ कार का प्रयोग इसी कारण से हुआ है। 'भूः भुवःस्वः' यह तीन लोक हैं। अध्यात्म में भूः स्थूल शरीर के लिए, भुवः सूक्ष्म शरीर के लिए तथा स्वः कारण शरीर के लिए प्रयु त किया गया है। बाहरी जगत और अंतर के तीनों लोकों में ॐ कार अर्थात ईश्वर सर्वव्याहृक्षत है। व्याहृतियों में इसी तथ्य का प्रतियादन है। 'तत्' का अर्थ है वह। 'सवितु' का भावार्थ है- प्रकाश तथा ऊर्जा से ज्ञात तथा वर्चस् से ओतप्रोत परमेश्वर।

'वरेण्यः' का भावार्थ है श्रेष्ठ, तेजस्वी, विनाशक, देव। इन चार श दों में परमब्रह्म परमात्मा के उन गुणों का वर्णन है, जो अध्यात्मवादी अपनाने का प्रयत्न करते हैं। भर्ग शब्द तेजस्विता का बोधक है। इस शब्द में प्रतिभा साहसिकता, तत्परता, तन्मयता जैसे तत्वों का समावेश है। भर्ग का एक भाव नष्ट करना भी है। अनैतिकता, अवांछनीयता जैसी दुष्प्रकृतियां अगर मनुष्य को घेरे रहें, तो मनुष्य माया

व पतन के गर्त में फंस जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए ऐसी प्रखरता का उद्भव होना चाहिए, जो अंतर के कष्टों तथा भीतर के कल्मषों से छुटकारा दिला सके।

सविता, वरेण्य, भर्ग के उपरांत चौथी विभूतिमत्रा का नाम है देव। ईश्वर को देव श द से संबोधित करने का मतलब यह है कि हम ईश्वर के परम भक्त बनें तथा उसके देवत्व की विशेषता में अनुगमन करें।

‘धीमहि’ शब्द का अर्थ है धारण करना। आदर्शों को व्यवहार में उतारना ही उनकी धारणा है। ईश्वर दयावान, सदा प्रसन्न चित्त, धैर्यवान, क्षमावान व सदा आनंदित रहने वाले हैं। सुख-दुख से निरलेप हैं। उनके इन्हीं गुणों को धारण करना चाहिए। प्रथम चरण में सविता तथा वरेण्य की तथा द्वितीय चरण में भर्ग तथा देव की अवधारणा का प्रशिक्षण है। गायत्री के अंतिम तृतीय चरण 'धियो यो नः प्रचोदयात्' के अंतर्गत परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि साधक अकेले नहीं, बल्कि समस्त जन समुदाय में, प्राणिमात्र में 'धी' तत्व की वृद्धि करे। 'नः' हम सबको और 'धियः' वृद्धियों को कहते हैं, इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि अपनी अनुग्रह वर्षा करें।

उपासना का उद्देश्य

गायत्री उपासना का उद्देश्य है व्यक्ति में ऐसे तत्व का विकास करना, जिससे उस पर परमात्मा की कृपा हो सके। गायत्री मंत्र के जाप से दैविक व भौतिक साधनों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। उपजाऊ भूमि में ही वर्षा के बादलों के अनुग्रह से हरियाली उपजती है। कठोर चट्टानों पर तो एक पत्ता भी नहीं उगता। गायत्री उपासक अपना पूरा ध्यान आत्मपरिष्कार में लगाता है। गायत्री मंत्र के प्रभाव स्वरूप मनुष्य तामसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर परमपिता परमेश्वर से एकीकार होने के मार्ग पर अग्रसर होता है।

उपासना की विधि

- स्नानाआदि से निवृत्त होकर सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके गायत्री मंत्र का जाप करने से बुद्धि ते। होती है।
- पुष्प व मोठा नेवेद्य अर्पित करके ऊनी या कुशासन पर बैठकर तुलसी या रूद्राक्ष की माला पर जाप करें।
- गायत्री मंत्र धर्म व अर्थ दोनों की वृद्धि करने वाला है।
- जाप करने से शरीर आरोग्य रहता है। काया के कष्ट मिटते हैं।
- लगातार जाप करने से मोक्ष की प्राहि्षत होती है
- विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे याददाश्त बढ़ती है तथा माता सरस्वती की कृपा से ज्ञान में वृद्धि होती है।

घरों में पत्थर लगाने का चलन बहुत बढ़ गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पत्थर नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं...

घर में पत्थर लगा हो तो...

पत्थर के बने मकान, दीवार या स्टोन पिलर का प्रतिनिधित्व म गल ग्रह करता है। शनि और राहु ग्रह मंगल के शत्रु होते हैं। ऐसे में निश्चित समझना चाहिए कि जब शनि दुश्मन बना हुआ हो, तोऐसे मकानों में रहने वाले या उपयोग में लेने वाले सुखी रह ही नहीं सक ते। उसी प्रकार छाया ग्रह राहु भी वहां रहने वालों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। यदि ऐसे पत्थरों से बने मकानों में अंधेरा हो, तो वहां भूत-प्रेत निवास करना पसंद करते हैं या यूं कहे कि ऐसे घरों में इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि वहां भूत-प्रेत होने का अहसास होता है। एक बात याद रखनी चाहिए, अगर कोई आदमी वास्तु के अनुसार बने भवन में रहता है, उसके ग्रह निर्बल हों, तो भी उसका जीवन सामान्य ढंग से सुख-शांति से व्यतीत होता है।

पत्थर अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है और मिट्टी बुध का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में पत्थर अहंकारी बनाता है और मिट्टी धार्मिक पवित्रता प्रदान करती है। वे मकान, जिन्हें पत्थरों को मिट्टी से जोड़कर बनाया जाता है, वहां बुध और मंगल के प्रभाव का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है। यदि किसी घर के सामने पत्थर का बना आशियाना हो, तो उस घर में रहने वाला परिवार कभी

भी किसी भी तरह तरक्की नहीं कर सकता। उनके बच्चों को पढ़ाई में बहुत विघ्न, बाधाएं आती हैं। यदि पत्थरों से बना आशियाना पुराना, क्षतिग्रस्त या टूटा-फूटा हो, तो उसमें रहने वालों के साथ-साथ आसपास के घरों में रहने वाले भी अभाग्य का शिकार होते हैं।

यदि किसी घर के ठीक सामने कोई बड़ा पत्थर या स्टोन पिलर हो, उस घर का मुखिया लड़ाई-झगड़ा पसंद करने वाला, आगे बढ़कर दुश्मनी मोल लेने वाला होता है। यदि कोई बड़ा पत्थर घर के मुख्यद्वार के एकदम सामने आता हो, ऐसे घर में रहने वाले दंपति के आपसी संबंधी सौहार्दपूर्ण नहीं रहते। किसी घर में बड़ा पत्थर हो या बड़े पत्थर का बना कोई स्लैब हो या घर के सामने छोटी पहाड़ी हो, ऐसी स्थिति में उसका मुखिया उसके बच्चे भय में रहते हैं। कई

वास्तु शास्त्र



मकान बहुत सुंदर बनाए जाते हैं, पर बचत के लिए मकान और चारदीवारी के बीच में पत्थर के स्लैब लगाए जाते हैं। ऐसे घरों में रहने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय और व्यापार में भी सफलता नहीं मिल पाती।

यदि कोई भवन या उसकी कंपार्टमेंट वाल पत्थरों से बनी हो, तो इस दोष को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि उसे सीमेंट या मिट्टी से ढंक देना चाहिए अर्थात प्लास्टर कर देना चाहिए।

आपकी कार का रंग

यदि आप कार खरीदने जा रहे हैं, तो उसके रंग का चयन अपनी शुभता के अनुसार करें। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव और चतुर्थेश पर पड़ने वाले ग्रह योगों से आप अपने वाहन के रंग के बारे में जान सकते हैं। आपके वाहन का रंग किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय करने के लिए चतुर्थ भाव एवं चतुर्थेश पर जिस ग्रह का प्रभाव हो, उससे संबंधित ग्रह के अनुसार वाहन के रंग का निर्णय करें। यदि सूर्य या मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव एवं चतुर्थेश पर प्रभाव हो, तो लाल रंग का वाहन यदि चंद्रमा एवं शुक्र का प्रभाव चतुर्थ भाव एवं चतुर्थेश पर हो, तो हरे एवं आसमानी रंग का वाहन, यदि गुरु का प्रभाव वाहन से संबंधित भाव एवं भावेश पर हो, तो पीले रंग का वाहन, यदि शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव एवं चतुर्थेश पर युति अथवा दृष्टि के द्वारा हो, तो नीले गहरे रंग वाली कार लें। चंद्र एवं शुक्र के प्रभाव के साथ ही अन्य ग्रह का प्रभाव होने पर वाहन का रंग हल्का एवं चमकीला लें।

में मंगल व अष्टमेश में सूर्य हो तो दाह ज्वर होता है। चंद्रमा शीत कफ ज्वर, बुध पित्त ज्वर व शनि वात ज्वर के कारक ग्रह हैं।

अनुभूत कारण : निरंतर या आए दिन ज्वर से पीड़ित रहने वाले कई जातकों की कुंडलियों में देखा गया है कि जब उनके राहु में बुध की अंतरदशा चली तो वह बुखार, टाइफाइड व अन्य ज्वरों से लगातार परेशान रहा और आर्थिक तथा घरेलू मुश्किलों से त्रस्त हो गया।

ज्योतिषीय उपचार : जातक की कुंडली व दशा-अंतरदशा पर विचार करने के बाद जिस ग्रह के कारण ज्वर हो रहा हो, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान और मंत्र जाप आदि करना चाहिए। जातक स्वयं करे तो बेहतर और यदि किसी कारण से स्वयं नहीं कर सके तो घर का अन्य व्यक्ति उसके नाम से दान व मंत्रों का जाप कर सकता है। ज्वर पीड़ित के कक्ष में निरंतर गुगुलु की धूप और संबंधित ग्रह की मंत्र ध्वनि लाभकारी होती है।



अंतरदशाओं से ज्वर

ज्वर (बुखार) के कई भेद व उपभेद हैं। यह व्याधि सामान्य होती है, किंतु परिणाम कई बार भयावह हो जाते हैं। सूर्य, चंद्र, बुध व शनि ज्वर के प्रमुख कारक ग्रह हैं। नीच के सूर्य व नीच के ही चंद्रमा की महादशा में या केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा अथवा शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा में बुखार या ज्वर भयानक रूप ले लेता है।

ज्योतिषीय कारण : गुणाकर, वराहाचार्य, श्रीपति आदि ने माना है कि सूर्य, चंद्र एवं बुधशनि प्रधान रूप से ज्वर के कारक ग्रहों में होते हैं। नीचस्थ सूर्य व नीचस्थ चंद्र की महादशा में अथवा केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा या शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा हो तो जातक बुखार से जकड़ जाता है।

कौन सा ज्वर : ज्योतिष का मत है कि लग्नेश व षष्ठेश सूर्य युक्त हो तो जातक को ज्वर का भय होता है। षष्ठ व अष्टम में सूर्य हो या अष्टम में चंद्रमा राहु युक्त हो, अष्टमेश चंद्र या राहु या केतु युक्त हो तो तो चौथिया (चार दिन के अंतराल वाला) ज्वर होता है। लग्न

दुख नाशक चौपाइयां

संपदा प्राप्ति के लिए

जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं सुख संपति नाना विधि पावहि।

आमदनी के लिए

विश्व भरन-पोषन कर जोई ताकर नाम भरत अस होई

कार्य विघ्न हरण के लिए

सकल विघ्न व्यापहिं नाहिं तेही राम कृपाकर चितवहिं जेही।

संकट नाश के लिए

दीन दयाल विरद संभारी

हरहु नाथ मम संकट भारी

रोग शांति के लिए

दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहु नहिं व्यापा

ग्रह शांति के लिए

नाम प्रभाउ जान सिव नीको कालकूट फलु दीन अमी को

मनोकामना पूर्ति के लिए

सुनु सिय सत्य असीस हमारी पूजहिं मनकामना तुम्हारी।

रक्षा कवच के लिए

मामभिरक्षय रघुकुल नायक घृत वर चाप रुचिर कर सायक।



उपाय शनि देव के



जन्म कुंडली में यदि षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादश शेष हों या द्वितीयेश-सप्तमेश होने के कारण मारकेश हों तो कष्टकारक होते हैं। व्यक्ति को शनि की महादशा, अंतर्दशा या अशुभ गोचरीय परिभ्रमण दृष्ट्या-सादेसाती के समय प्रतिकूल फल देते हैं। इससे बचने के लिए आप इनमें से कोई एक उपाय कर लें। इससे अशुभ फलों में कमी आएगी-

- काले घोड़े की नाल की अंगूठी दायें हाथ की मध्यमा अंगुली में पहनें या काले कुत्ते को सायंकाल रोटी खिलाने से भी लाभ मिलेगा।
- शनिवार को शनि स्रोत का पाठ करें। शनिवार का व्रत भी रखें तो ज्यादा अच्छा है।
- शनि के वैदिक मंत्र (शन्नोदेवीरभिष्टयादि) या तांत्रिक मंत्र (ऊं प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः) की दो माला प्रतिदिन जपें।
- शनिवार को पीपल के वृक्ष को सींचें, वृक्ष यदि मंदिर परिसर में हो तो ज्यादा अच्छा है।

- हनुमान जी की पूजा-अर्चना करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकाण्ड का पाठ या हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। शनिवार या मंगलवार का व्रत कर सकते हैं।

- शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार समय-समय पर करें। (काले तिल, उड़द, कुलथी, खाद्य तेल, काला वस्त्र, छात्रा कम्बल, जूते-चप्पल, लोहे की वस्तुएं, स्टील के बर्तन आदि)।

- काले या गहरे नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग यथासंभव नहीं करें।
- शनि की वस्तुओं का दान ग्रहण नहीं करें।

- सूर्य को अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
- कोई नया कारोबार, जोखिम वाला काम, ज्यादा रकम का इन्वैस्टमेंट आदि नहीं करें।

इसके अतिरिक्त सात्विक आहार-विहार, विनम्र व्यवहार, क्रोध पर नियंत्रण, लोभ-लालच से परहेज, अच्छी संगति, सकारात्मक विचार, प्रोपेकार, शरीर और मन की पवित्रता, ईश्वर भक्ति स्वाध्याय आदि से समस्त ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं जिनमें शनि भी शामिल है।

सुंदर के साथ शुभ भी होते हैं निशान

बाएं पैर की पहली और आखिरी उंगली फड़के तो आपको लाभ होगा। दाएं पैर की उन्हीं उंगलियों का फड़कना अशुभ होता है।

पांव की पिंडली शनि और बुध नक्षत्र के अधीन आती है। इसके फड़कने से काम में बाधा आती है और यह शत्रु के पैदा होने का संकेत है। दायां घुटना फड़के तो अशुभ और बायां फड़के तो शुभ होता है।

बायां पांव फड़कना : शुभ होता है। दायां पांव फड़कने से मुसीबतों का अंत होता है। बाईं जांघ के फड़कने से दोस्त से सहायता मिलती है, जबकि दाईं जांघ फड़कने से शत्रु

शांत होते हैं। दाएं हाथ का अंगूठा फड़कने से शुभ समाचार मिलता है, जबकि बायां फड़के तो नुकसान होता है।

शरीर के तिल या मस्से : उनका संबंध शनि व राहु से माना जाता है। शनि धीरे-धीरे फल प्रदान करता है और राहु अचानक ही शुभ या अशुभ फल दे देता है।

दाएं गाल पर तिल : शुभ होता है।

टुंडी पर तिल प्यार में कमी का सूचक है।

दाईं आंख पर तिल : खूब प्यार मिलता है। बाईं आंख पर तिल होने से प्यार में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाँहों

पर तिल होने से घूमने-फिरने के मौके मिलते हैं। बांह पर तिल होना हमेशा शुभ माना जाता है। गाई बांह पर तिल हो तो अपार धन मिलता है। बाईं तरफ हो तो धन के साथ-साथ पुत्र की प्राप्ति होती है। होंठ पर तिल व्यक्ति के लालची स्वभाव दर्शाता है।

गले पर तिल : ऐसे जातक की धार्मिक कार्यों में अधिक रूचि होती है। कान पर तिल होने से धन मिलता है। गर्दन पर तिल आलस्य की निशानी है। अंगूठे पर तिल उत्तेजना की निशानी है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से तेज मिजाजा का होता है।



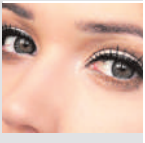
सुझाव

मानव शरीर के बारे में रोचक तथ्य

इन्सानी शरीर दुनिया की सबसे पेचीदा मशीन है। हमारे शरीर के बारे में कई ऐसी बातें हैं, जिनसे हम शायद ही वाकिफ हों। इस शरीर से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं, जो वाकई हैरान करने वाले हैं। आइए इस स्लाइड शो के जरिये इन्सानी शरीर के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं।

आंखों की कहानी

हमारे यह हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसका आकार कभी नहीं बदलता। जन्म से लेकर मृत्यु तक आंख का आकार एक समान रहता है। हालांकि, समय के साथ-साथ इसके लेंस का आकार जरूर मोटा होता जाता है। हमारे कान और नाक मृत्यु पर्यंत बढ़ते रहते हैं।



दिमाग की पेचीदगी

मनुष्यों में मस्तिष्क को पूरी तरह से विकसित होने में करीब 25 वर्ष लगते हैं जबकि फेफड़ों को पूरी तरह से विकसित होने में 18 से 22 वर्ष तक का समय लगता है।



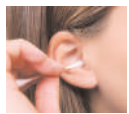
नाखूनों की बात

महिलाओं के नाखूनों की तुलना में पुरुषों के नाखून तेज गति से बढ़ते हैं। ऐसा हार्मोन के कारण होता है। साथ ही नाखून के बढ़ने की गति गर्मियों में अधिक तेज होती है क्योंकि शरीर द्वारा धूप का इस्तेमाल कर विटामिन डी बनाने से बहुत तेज हो जाती है।



इतना बुरा नहीं कान का मैल

कान का मैल हमारे रक्षा तंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। यह कानों को कई प्रकार के बैक्टीरिया से बचाती है। हालांकि कुछ लोगों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं होती पर यह हमारे शरीर के लिए फायदेमंद ही होती है।



किडनियों के आकार में होता है अंतर



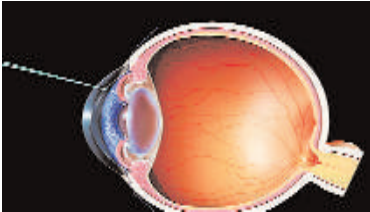
मनुष्य का दाईं किडनी, बाएं किडनी से बड़ी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाएं किडनी के पास दिल होता है।

आंखें कुदरत की ओर से दी गई सबसे कीमती उपहार हैं। ये जितनी कीमती हैं, उतनी ही संवेदनशील भी हैं। इसलिए तो लोग आंखों का विशेष ख्याल रखते हैं और थोड़ा भी सरदद होने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करवाते हैं। पहले लोग आंखों की समस्या से निजात पाने के लिए चश्मा पहनते थे। लेकिन चश्मा एक बार चढ़ गया तो जिंदगी भर लगाना पड़ता है। लेकिन विकसित होती तकनीक ने आंखों के उपचार को आसान कर दिया है। आजकल डॉक्टर चश्मा लगाने वाले को लेसिक सर्जरी करने की हिदायत देते हैं और लोग लेसिक सर्जरी का फायदा भी उठा रहे हैं। लेसिक सर्जरी कराने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। आइए इस लेख में लेसिक सर्जरी के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं।

क्या है लेसिक सर्जरी

जो लोग चश्मा पहनते हैं और जिनका पावर -1 से -10 के बीच है, उन्हें तुरंत आंखों की लेसिक सर्जरी करवानी चाहिए। जांच में देख लें कि आपके कॉर्निया की थिकनेस कैसी है। जितनी अधिक थिकनेस होगी इस सर्जरी का फायदा उठना अधिक होगा। साथ ही लेसिक सर्जरी की सबसे अच्छी बात है कि ये अन्य दूसरी सर्जरी की तुलना में ज्यादा आसान और बेहतर है। यह सस्ती होती है और इसमें कॉर्निया को नुकसान पहुंचाने का खतरा न के बराबर होता है। जबकि दूसरी सर्जरी में कॉर्निया पर खतरा ज्यादा रहता है।

लेसिक सर्जरी के फायदे



लेसिक सर्जरी 30 मिनट या उससे कम समय में हो जाती है। साथ ही यह सर्जरी आंखों के लिए काफी प्रभावी और कारगर मानी गई है, जिस कारण अधिकतर लोग आंखों के लिए लेसिक सर्जरी करने की हिदायत देते हैं। 92-98% लोग आंखों की समस्या से निजात पाने के लिए लेसिक सर्जरी का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि ये आंखों की दृष्टि के लिए काफी फायदेमंद होती है और किसी भी अन्य सर्जरी की तुलना में आसान और किफायती होती है। लेसिक सर्जरी दृष्टि से जुड़ी सभी समस्याओं और खतरों को काफी हद तक दूर कर देती है।

हाई ब्लड प्रेशर बीमारी के लक्षण और निजात पाने के उपाय



कभी ऐसा माना जाता था कि उच्च रक्तचाप केवल बुढ़ापे की बीमारी है, परंतु अब स्थिति तेजी से बदल रही है। 30 साल का युवक भी आज यह कहता सुनाई दे सकता है कि उसे ब्लड प्रेशर है यानी उसका रक्तचाप सामान्य से अधिक है।

शारीरिक क्रिया के दौरान अशुद्ध खून पहले दिल के एक भाग से फेफड़ों में प्रवेश करता है, फिर वहां से शुद्ध होकर दिल में वापस आ जाता है। फिर दिल का दूसरा भाग खून को पंप करके उसे शरीर के बाकी हिस्सों में भेजता है। दिल जब खून को पंप करता है तो यह क्रिया एक उचित दबाव के साथ की जाती है। जिससे कि आखिरी दौर पर पहुंचने के बाद भी खून में इतना दाब बना रहा सके कि वह फिर से दिल तक लौट कर आ सके। इस पूरी प्रक्रिया में धमनियों की भित्ति पर जा दाब स्थापित होता है वही रक्तचाप है।

साधारण तौर पर यह दाब 120 होता है जिसे ऊपरी दाब या सिस्टोलिक कहते हैं। दो बार पंपिंग करने के बीच में जो समय होता है उतने समय में दिल आराम कर लेता है यह समय करीब आधा सेकंड का होता है, इसी दौरान धमनियों पर दाब काफी घट जाता है और लगभग 90 हो जाता है, इसे निचला दाब या डायस्टोलिक कहते हैं। यही स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके बढ़ने का मतलब यह होता है कि दिल पर बोझ पड़ रहा है।

जब तक धमनियां एकदम चिकनी और खुली रहती हैं तब तक खून एक निश्चित और स्थिर दबाव से बहता रहता है। जब तक शरीर की धमनियां व खून की नलिकाएं अपने स्वाभाविक रूप में रहती हैं यानी जब तक ये लचीली रहती हैं, इनके छेद खुले रहते हैं तब तक खून को आगे बढ़ाने के लिए दिल को जरूरत से ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ती और रक्त अपनी स्वाभाविक गति में हृदय से निकलकर धमनियों और खून की नलिकाओं की ओर से शरीर के हर भाग में पहुंचता रहता है। लेकिन जब धमनियां कठोर और संकरी हो जाती हैं तो खून को शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाने के लिए दिल को जरूरत से ज्यादा दबाव डालकर उन संकरी और कठोर धमनियों में खून को धकेलना पड़ता है।

साधारण तौर पर उच्च रक्तचाप का कोई लक्षण नहीं होता और व्यक्ति को काफी समय तक इसका पता ही नहीं चलता है, लेकिन बाद में अनेक लक्षण सामने आने लगते हैं जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, शिथिलता, सांस में परेशानी, नौद न आना, जरा सी मेहनत करने पर सांस फूलना, नाक से खून निकलना आदि।

उच्च रक्तचाप का एकमात्र कारण हमारा अनियमित जीवन और हमारे खाने-पीने की आदतों में असावधानी है। खान-पान में संयम न बरतने से कोलेस्ट्रॉल (एक प्रकार की वसा) धमनियों की भित्ति पर चिपक जाती है जिससे धमनियां संकरी होने लगती हैं। नतीजतन दिल का खून को पंप करने का बोझ बढ़ जाता है।

अनियमित जीवन तथा खानपान के साथ-साथ और भी कई कारण उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी हैं। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या भय आदि मानसिक विकार भी उच्च रक्तचाप का कारण होते हैं। बार-बार या जरूरत से अधिक खाना भी उच्च रक्तचाप का कारण हो सकता है। मैदा से बने खाने के पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, आचार, मिठाईयां, मांस, चाय, सिगरेट व शराब आदि का सेवन करने से भी उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है। नियमित खाने में रेशे, कच्चे फल, सलाद का अभाव, श्रमहीन जीवन, व्यायाम का अभाव, पेट और पेशाब संबंधी पुरानी बीमारी से भी उच्च रक्तचाप का रोग हमें अपनी गिरफ्त में ले सकता है।

आजकल हम लोग जो भोजन करते हैं वह हमारी सेहत के लिए कतई ठीक नहीं है। बारीक पिसे आटे की रोटियां, पालिश किया हुआ चاولे, घी, तेल, मसालेयुक्त सब्जियां, चाय, कॉफी, शीतल पेय, केक, बिस्किट ब्रेड, बरगर, पिज्जा जैसे भोजन आज हमारी आधुनिक जीवन शैली में शामिल हैं। लेकिन यही उच्च रक्तचाप और उससे संबंधित कई बीमारियों की जड़ है। यदि चोकर युक्त मोटे आटे की रोटी, छिलके समेत फल और सब्जियां, पालक, मेथी, बथवा, तुरई, लोकी, पेठा, नींबू आदि को हम अपने रोजाना के भोजन में शामिल कर लें तो हम उच्च रक्तचाप के साथ-साथ अन्य बीमारियों से भी मुक्त रह सकते हैं।

खाने-पीने की अच्छी आदतों के साथ-साथ यदि हम अपनी रोजाना की दिनचर्या पर भी ध्यान दें जैसे रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना,

सुझाव

कैंसर से बचाये टमाटर



कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से बचने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं। ऐसे में डॉक्टर भी कैंसर से बचाव के लिए सही खान-पान और सब्जियों और फलों को खाने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं खानपान के दौरान कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं । जिनको खाने से आप कैंसर के सेल्स को पनपने से आसानी से रोक सकते हैं। जी हां टमाटर ऐसा ही खाद्य पदार्थ है जिसे ना सिर्फ सलाद के रूप में बल्कि हर सब्जियों में मिक्स करके और जूस के रूप में भी लिया जा सकता है। टमाटर के फायदे कई हैं। इन फायदों में कैंसर से बचाव सबसे प्रमुख लाभ है। आइए जानें कैसे कैंसर से बचाये टमाटर।

» टमाटर बहुत ही फायदेमंद है, इसे खाकर ना सिर्फ कई गंभीर बीमारियों को पनपने से रोका जा सकता है बल्कि इससे त्वचा में भी निखार लाया जा सकता है।

» जो लोग वजन बढ़ने से परेशान रहते हैं, उनका वजन कम करने में भी टमाटर बहुत लाभदायक है। इन सब फायदों के अलावा टमाटर में कैंसर को रोकने की क्षमता भी पाई जाती है।

» तमाम शोर्धों में भी ये साबित हो चुका है कि यदि आप नियमित रूप से एक सप्ताह में कम से कम दस बार टमाटर का सेवन करते हैं तो आपमें कैंसर के होने की संभावनाएं लगभग 45 फीसदी घट जाती हैं।

» यदि आप पेट के कैंसर को पनपने से रोकना चाहते हैं तो टमाटर को सलाद में लेना चाहिए। टमाटर को प्रतिदिन सलाद में लेने से आप पेट के कैंसर के होने वाले खतरे का लगभग 60 फीसदी तक रोक सकते हैं।

» तमाम शोर्धों के परिणामों में निकला है कि टमाटर में लाइकोपीन नामक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि विभिन्न प्रकार के कैंसर को रोकने में ना सिर्फ फायदेमंद है। बल्कि इस पदार्थ से कैंसर के पनपने की आशंकाएं भी बहुत हद तक खत्म हो जाती है।

» इतना ही नहीं हरे टमाटर की बजाय लाल टमाटर अधिक फायदेमंद होता है और उसमें फ्राई होने के बाद भी लाइकोपीन को अच्छी तरह से आब्जर्व करने की क्षमता होती है।

» जैसे आम खाद्य पदार्थों को फ्राई करने के बाद उनके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। लेकिन टमाटर के साथ ऐसा नहीं है। टमाटर को तेल में फ्राई करने के बाद भी पोषक तत्व ज्यों के त्यों रहते हैं।

» गौरतलब है कि कैंसर को कम करने वाले लाइकोपीन तत्व के अलावा टमाटर में नियासिन, विटामिन बी6 पोटेशियम और फॉलेट जैसे उपयुक्त पदार्थ भी मौजूद होते हैं। जिन्हें दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बेहद जरूरी हैं।

» टमाटर में कैंसर को रोकने के तत्वों के अलावा एंटी एंजिंग कंपाउंड्स जैसे- आईकोपीन व बीटा कैरोटिन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि स्वस्थ रखने में और बीमारियों से बचाने में लाभकारी हैं। गौरतलब है कि बीटा कैरोटिन शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। जो कि हड्डियों के कैंसर और त्वचा संक्रमण और फॉलेट जैसे

» पुरुष यदि प्रतिदिन टमाटर खाएं तो उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना कम रहती है। इतना ही नहीं जिन लोगों को द्यूमर होता है, उनके द्यूमर को कम करने में और ट्यूमर को बढ़ने से रोकने में भी लाभकारी है।

» जिन लोगों में आनुवांशिक रूप से कैंसर का खतरा होता है। टमाटर उसे खतरे को कम करने में कारगर है।

HIV को न करें नजरअंदाज, दिखने लगे ये लक्षण तो तुरत करवाएं जांच

एचआईवी एक ऐसा वायरस है, जिस वजह से एड्स होता है। भले ही अब इसका इलाज संभव हो चुका है लेकिन इस बीमारी में कुछ सावधानियां बरतने की जरूर होती है। बहुत लोगों को तो इसके शुरूआती संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, जिस वजह से यह बीमारी बढ़ती चली जाती है। इसलिए बेहतर है कि इन लक्षणों को पहचानकर समय पर एचआईवी का इलाज करवाया जाए। हम आपको इसके साधारण दिखने वाले कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए।

थकान : कई बार बैठे रहने पर भी थकान महसूस होने लगती है और शरीर में दर्द होने लगता है इस थकान को हल्के में न लें क्योंकि यह एचआईवी का शुरूआती लक्षण होता है जिसे अवसर लोग अनदेखा कर देते हैं।

दस्त : अगर एक हफ्ते या इससे ज्यादा समय से पतले दस्त हो रहे हो तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। बहुत से लोग इन्हें मामूली दस्त समझकर कुछ दवाईयों और घरेलू नुस्खा का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें क्योंकि ऐसे दस्त पर दवाईयां भी कोई असर नहीं कर पाती।

शरीर पर धब्बे : एड्स होने पर मुंह, आंखों के नीचे और नाक पर लाल, नीले और बैंगनी रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, जिनकी शुरूआत चेहरे से होती है। इन्हें मामूली धब्बे न समझे बल्कि डॉक्टरी जांच करवाएं।

बार-बार बुखार : अगर हर दो दिन बाद बुखार आ जाए तो इसे मामूली बुखार न समझें बल्कि डॉक्टर की सलाह लें क्योंकि यह एच आईवी के लक्षण हो सकते हैं।

रेसिपी



विधि

चावल को साफ करके धो लें. फिर इसे पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें । सोयाबीन की बड़ियों को गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगोएं । फिर बड़ियों को पानी से निकाल 2 से 3 बार धो लें । अब गैस पर पैन में तेल या घी गर्म करें. इसमें जीरा, तेज पता, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग का तड़का लगाएं । फिर पैन में प्याज और हरी मिर्च डालकर मध्यम आंच पर पकाएं । जब प्याज रंग हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें गाजर, मटर, हल्दी और नमक डालकर 2 मिनट तक भूनें । अब चावल को पानी से निकालकर पैन में डालें । फिर सोयाबीन की बड़ी डालकर मिक्स करें । इसके बाद पैन में लगभग 3 कप पानी डालकर ढक दें । अब धीमी आंच पर चावल को पकने दें । लगभग 15 मिनट में चावल कूट जाएंगे। फिर पैन से ढक्कन हटाकर पुलाव को चलाएं । अब गैस बंद कर दें. तैयार है सोया पुलाव । इसे हरी धनिया पत्तियों से गार्निश करके गर्मागर्म सर्व करें ।

लखनवी पनीर कबाब



विधि

पनीर को लंबा काट लें। इन्हें एक प्लेट में रखकर चाट मसाला, लालमिर्च, गरम मसाला, अदरक का पेस्ट और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह से मिलाएं । अब एक बाउल में मैदा, सूजी, लालमिर्च पाउडर, गरम मसाला, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और पानी डालकर गाढ़ा घोल बना लें। कढ़ाही में तेल गर्म करें। अब एक प्लेट में थोड़ी सूजी, मैदा, काले और सफेद तिल फैला लें। गाढ़े घोल में पनीर को डिप करें और उस पर तिल वाला मिश्रण सपेटें। पनीर को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक तलें। तलने के बाद ऊपर से चाट मसाला छिड़कें और नींबू व प्याज के साथ इसे गर्मागर्म सर्व करें।



संपादकीय

यूपीआई 'मुफ्त' नहीं

प्रधानमंत्री

मोदी जो दिंदोरा पीट रहे थे और देश की जनता को आपवस्त कर रहे थे, उसका ढोल फट चुका है और सच सामने है। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के जरिए ऐलान कराया है कि अब डिजिटल भुगतान (‘यूपीआई’ ‘मुफ्त’ नहीं होगा, बल्कि प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आम ग्राहक, आम उपभोक्ता, आम आदमी को जेब कटेगी। अब यह यथार्थ भी सामने आ सकता है कि नकदी लेन-देन की ओर वापसी होने लगे। आम आदमी को यूपीआई लेन-देन की लत लग चुकी थी। उसे यह व्यवस्था आसान और सहज लगती थी। वह औसतन हर भुगतान यूपीआई के जरिए ही करने लगा था। फुटपाथ के पास रेहड़ी-पटरी, चायवाला अथवा टोकरी में फल बेचने वाली निरक्षर-सी महिला ‘स्कैन’ के जरिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करने लगे थे। इसकी लोकप्रियता, व्यापकता का पुख्ता प्रमाण यही है कि यूपीआई से साल भर में 314.23 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन किया गया। यूपीआई इस्तेमाल करने वालों की संख्या 24,162 करोड़ बताई गई है। यूपीआई के जरिए रोजाना औसतन 66 करोड़ बार लेन-देन होता है। करीब 67 फीसदी भुगतान

2000 रुपए से अधिक का किया गया, शरक सरकार ऐसा करने वालों की संख्या मात्र 4 फीसदी और 2000 रुपए से कम वाले 96 फीसदी बता रही है। दरअसल इन 4 फीसदी का मूल्य ही 67 फीसदी है। बेशक भारत सरकार की अधिसूचना में उल्लेख है कि व्यक्ति से व्यक्ति अथवा 2000 रुपए तक का लेन-देन करने

सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के जरिए ऐलान कराया है कि अब डिजिटल भुगतान (यूपीआई) ‘मुफ्त’ नहीं होगा, बल्कि प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आम ग्राहक, आम उपभोक्ता, आम आदमी की जेब कटेगी। अब यह यथार्थ भी सामने आ सकता है कि नकदी लेन-देन की ओर वापसी होने लगे। आम आदमी को यूपीआई लेन-देन की लत लग चुकी थी। उसे यह व्यवस्था आसान और सहज लगती थी। वह औसतन हर भुगतान यूपीआई के जरिए ही करने लगा था। फुटपाथ के पास रेहड़ी-पटरी, चायवाला अथवा टोकरी में फल बेचने वाली निरक्षर-सी महिला ‘स्कैन’ के जरिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करने लगे थे। इसकी लोकप्रियता, व्यापकता का पुख्ता प्रमाण यही है कि यूपीआई से साल भर में

314.23 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन किया गया। यूपीआई इस्तेमाल करने वालों की संख्या 24,162 करोड़ बताई गई है। यूपीआई के जरिए रोजाना औसतन 66 करोड़ बार लेन-देन होता है। करीब 67 फीसदी भुगतान 2000 रुपए से अधिक का किया गया, बेशक सरकार ऐसा करने वालों की संख्या मात्र 4 फीसदी और 2000 रुपए से कम वाले 96 फीसदी बता रही है। दरअसल इन 4 फीसदी का मूल्य ही 67 फीसदी है। बेशक भारत सरकार की अधिसूचना में उल्लेख है कि व्यक्ति से व्यक्ति अथवा 2000 रुपए तक का लेन-देन करने वालों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क वैसे भी दुकानदार, व्यापारी, यानी मर्चेन्ट को भरना होगा, लिहाजा इस शुल्क को ‘एमडीआर’ का नाम दिया गया है। यह बड़ी हास्यास्पद और बेवकूफ बनाने वाली व्यवस्था है। किराने, दूध-दही का दुकानदार या दवाओं की दुकान अथवा टीवी, फ्रिज, मोबाइल के शोरूम, अंततः, यह ‘हर्जाना’ क्यों भुगतेंगे? बैंक कितनी निगरानी रख सकते हैं? वे किसी को भुगतान की प्रणाली के लिए बाध्य नहीं कर सकते। एनपीसीआई ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 फीसदी और 75,000 रुपए या अधिक के बड़े लेन-देन के लिए अधिकतम शुल्क 300 रुपए तय किया है। आपको अब रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने और कृषि इनपुट सरीखे जरूरी भुगतान पर 5 रुपए (प्रति लेन-देन) शुल्क देना होगा। स्कूल-कॉलेज की फीस 2000 रुपए से अधिक की है, तो उस पर 300 रुपए की दर देनी होगी, तो आम आदमी पर बोझ कैसे नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी? संभव है कि डिजिटल भुगतान के मद्देनजर जितने लाखों करोड़ रुपए का लेन-देन हो रहा है, उससे टेक्स वसूलने का लालच सरकार ने महसूस किया होगा। यह सवाल भी सामने होगा कि यूपीआई के व्यापक, विविध नेटवर्क पर 20,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च क्यों किए जाएं? हर साल के बजट में 2000 करोड़ रुपए क्यों तय किए जाएं? क्यों न इसका कुछ बोझ और प्रभार देश की जनता के साथ साझा किया जाए? कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अब मोदी सरकार का ‘वैश्विक थाली बजाव प्रचार’ बेनकाब हो गया है। सरकार की तबज से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया है कि आखिर यह ‘हर्जाना’ थोपने की नौबत क्यों आई? बेशक हमारा यूपीआई लेन-देन 11 अन्य देशों में भी प्रचलित है और 23 अन्य देशों के साथ समझौते विचाराधीन हैं। यह विदेश नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन चिंता आम भारतीय की होनी चाहिए, जो बहुधा गरीब है, न्यूनतम आय वाला है और राजनीतिक दलों को वोट देकर सत्ता में पहुंचाते हैं। उन पर करोड़ों बहुत मार है। बैंक से एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर फीस है। बैंक बैंलेस तय सीमा से कम है, तो चार्ज लगता है। चेकबुक का औसतन एक पन्ना 2-5 रुपए का है। चेक बाउंस होने पर 250-500 रुपए तक का जुर्माना है। यदि बैंक खाता बंद कराना है, तो भी 200 रुपए फीस देनी पड़ती है। आम आदमी औसतन हर वस्तु और सेवा पर परोक्ष रूप से जीएसटी भी देता है। और ऐलानिया कृपा यह है कि आम आदमी पर एमडीआर नहीं लगेगी। न बैंक गरीब हैं और न ही एनपीसीआई घाटे में है। उसके खाते में करीब 1800 करोड़ रुपए का मुनाफा जमा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार को दे रखे हैं। आम आदमी को क्यों चूस रहे हो, सरकार जी? बहरहाल इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। भारतीय नागरिकों को मुफ्त में भुगतान करने की सुविधा जारी रहनी चाहिए। सरकार ने मुफ्त में भगतान की सुविधा देकर भारतीय नागरिकों को एक बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाई थी, लेकिन अब इसमें फेरबदल करने से असंख्य भारतीयों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

का हिस्सा हो सकता है, लेकिन चिंता आम भारतीय की होनी चाहिए, जो बहुधा गरीब है, न्यूनतम आय वाला है और राजनीतिक दलों को वोट देकर सत्ता में पहुंचाते हैं। उन पर करोड़ों बहुत मार है। बैंक से एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर फीस है। बैंक बैंलेस तय सीमा से कम है, तो चार्ज लगता है। चेकबुक का औसतन एक पन्ना 2-5 रुपए का है। चेक बाउंस होने पर 250-500 रुपए तक का जुर्माना है। यदि बैंक खाता बंद कराना है, तो भी 200 रुपए फीस देनी पड़ती है। आम आदमी औसतन हर वस्तु और सेवा पर परोक्ष रूप से जीएसटी भी देता है। और ऐलानिया कृपा यह है कि आम आदमी पर एमडीआर नहीं लगेगी। न बैंक गरीब हैं और न ही एनपीसीआई घाटे में है। उसके खाते में करीब 1800 करोड़ रुपए का मुनाफा जमा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार को दे रखे हैं। आम आदमी को क्यों चूस रहे हो, सरकार जी? बहरहाल इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। भारतीय नागरिकों को मुफ्त में भुगतान करने की सुविधा जारी रहनी चाहिए। सरकार ने मुफ्त में भगतान की सुविधा देकर भारतीय नागरिकों को एक बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाई थी, लेकिन अब इसमें फेरबदल करने से असंख्य भारतीयों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

कुछ अलग

जीत से बड़ी हार

आज से 50-60 साल पहले कुछ मासिक पत्रिकाएं थीं, जैसे ‘सत्यकथा’, ‘मनोहर कहानियां’ और ‘सच्ची दुनिया’। हम लोग स्कूल में थे और किताबों-पत्रिकाओं की दुकानों पर ये भी डिस्प्ले की हुई होती थीं। इनको पढ़ना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन दसवीं या उसके बाद की कक्षाओं में पहुंचते-पहुंचते इनकी प्रकाश कहानी पढ़ ही लेते थे। मेरे बड़े मामा को इस तरह की जासूसी और जुर्म की पत्रिकाएं पढ़ने का बड़ा चस्का था। मेरी मां उनको कई बार टोका भी करती थीं। खैर, मामा की आदत जैसी थी, वैसी ही बरकरार रही। वह अंग्रेजी की ‘कारवा’, ‘रीडर्स डाइजैस्ट’ और ‘डिंडिया टुडे’ जैसी पत्रिकाएं भी खूब पढ़ते थे। मुझे कभी यह ‘सत्यकथा’, ‘मनोहर कहानियां’, ‘सच्ची दुनिया’ आदि पढ़कर अच्छा नहीं लगा। आजकल जिस तरह की खबरें रोजाना देखने-पढ़ने को मिल रही हैं, उससे यही लगता है कि इस दौर में तो वे पत्रिकाएं भी बहुत पीछे रह गई हैं।

दृष्टि कोण

नदियां किसी भी प्रदेश के लिए मात्र जल का स्रोत नहीं होतीं, वे उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामाजिक जीवन की रीढ़ होती हैं। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में यह महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहां की जलभाएएँ देश की ऊर्जा एवं जल आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ऐसे में टैंस नदी पर प्रस्तावित किशाऊ बहु उद्देश्यीय परियोजना को केवल एक बांध या बिजली परियोजना के रूप में देखना पर्याप्त नहीं। यह परियोजना हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक हितों, पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के भविष्य से गहराई से जुड़ी हुई है। 15 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच किशाऊ परियोजना को लेकर समझौता

हुआ। वर्षों से विभिन्न कारणों से अटक की यह परियोजना अब आगे बढ़ने की स्थिति में है। वर्तमान योजना के अनुसार लगभग 15624 करोड़ रुपए की लागत से 422 मेगावाट क्षमता की परियोजना विकसित की जानी है। इसमें लगभग 1562 मिलियन घन मीटर जल भंडारण की व्यवस्था होगी। परियोजना से लगभग 97 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने तथा करीब 1476 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का अनुमान है। किशाऊ परियोजना से हिमाचल को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष लाभ बिजली और उससे जुड़ा आर्थिक प्रतिक्रम है। मुख्यमंत्री सुखदेव सिंह सुक्खू के अनुसार परियोजना के चालू होने के बाद हिमाचल को लगभग 1200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। हिमाचल को परियोजना से

भुगतान-प्रणाली प्रदत्ता भुगतान करने वाले अथवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं ले सकते

शुल्क की आहट और यूपीआई का भविष्य

अंततः अमेरिकी दबाव ने असर दिखाया— यह निष्कर्ष आकर्षक जरूर है, लेकिन

14 सितंबर की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना को समझने के लिए थोड़ी सावधानी जरूरी है। अधिसूचना ने ₹2,000 तक के यूपीआई लेन-देन और रुपे डेबिट कार्ड भुगतान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क लगाने से बैंकों और भुगतान-प्रणाली प्रदाताओं को रोक दिया है। परंतु ₹2,000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर तत्काल कोई उपभोक्ता शुल्क लागू नहीं किया गया है; अधिसूचना ने केवल बड़े लेन-देन पर भविष्य में शुल्क या एमडीआर की संभावना के लिए रास्ता खुला छोड़ा है। फिर भी चिंता वास्तविक है। क्योंकि नीतियों का असर केवल उस शब्द से नहीं समझा जाता जो अधिसूचना में लिखा है; यह भी देखना पड़ता है कि उसके बाद बाजार का व्यवहार किस दिशा में जाता है। आज शुल्क सीधे ग्राहक से न लिया जाए, कल व्यापारी से लिया जाए और परसों व्यापारी उसे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में जोड़ दे—तो अंततः भार उपभोक्ता पर ही आ सकता है। आर्थिक व्यवस्था में लागत का कोई भी नया तत्व लंबे समय तक अपने मूल स्थान पर नहीं रहता; वह किसी न किसी रूप में कीमत, कमीशन या सेवा-शुल्क बनकर बाजार में फैल सकता है। सरकार का वर्तमान निर्णय यह नहीं कहता कि ₹2,000 से ऊपर का हर यूपीआई भुगतान अब शुल्कयुक्त हो गया है। अधिसूचना का स्पष्ट प्रावधान यह है कि ₹2,000 तक के यूपीआई लेन-देन पर बैंक या भुगतान-प्रणाली प्रदाता भुगतान करने वाले अथवा प्रणाली प्रदाता भुगतान करने वाले अथवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं ले सकते।

यह निष्कर्ष आकर्षक जरूर है, लेकिन 14 सितंबर की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना को समझने के लिए थोड़ी सावधानी जरूरी है। अधिसूचना ने ₹2,000 तक के यूपीआई लेन-देन और रुपे डेबिट कार्ड भुगतान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क लगाने से बैंकों और भुगतान-प्रणाली प्रदाताओं को रोक दिया है। परंतु ₹2,000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर तत्काल कोई उपभोक्ता शुल्क लागू नहीं किया गया है; अधिसूचना ने केवल बड़े लेन-देन पर भविष्य में शुल्क या एमडीआर की संभावना के लिए रास्ता खुला छोड़ा है। फिर भी चिंता वास्तविक है। क्योंकि नीतियों का असर केवल उस शब्द से नहीं समझा जाता जो अधिसूचना में लिखा है; यह भी देखना पड़ता है कि उसके बाद बाजार का व्यवहार किस दिशा में जाता है। आज शुल्क सीधे ग्राहक से न लिया जाए, कल व्यापारी से लिया जाए और परसों व्यापारी उसे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में जोड़ दे—तो अंततः भार उपभोक्ता पर ही आ सकता है। आर्थिक व्यवस्था में लागत का कोई भी नया तत्व लंबे समय तक अपने मूल स्थान पर नहीं रहता; वह किसी न किसी रूप में कीमत, कमीशन या सेवा-शुल्क बनकर बाजार में फैल सकता है। सरकार का वर्तमान निर्णय यह नहीं कहता कि ₹2,000 से ऊपर का हर यूपीआई भुगतान अब शुल्कयुक्त हो गया है। अधिसूचना का स्पष्ट प्रावधान यह है कि ₹2,000 तक के यूपीआई लेन-देन पर बैंक या भुगतान-प्रणाली प्रदाता भुगतान करने वाले अथवा प्रणाली प्रदाता भुगतान करने वाले अथवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं ले सकते।

देश दुनिया से

कॉर्पोरेट जगत में नारी शक्ति का बढ़ता कद

परिवर्तित समय के साथ महिलाओं की भूमिका में भी ख़ासा बदलाव आया है। कभी घर की चारदीवारी तक सीमित रहने वाली नारी आज प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है। इसका ज्वलंत प्रमाण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट है, जिसके अनुसार हाल के वर्षों में कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व और निदेशक मंडलों (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स) में महिलाओं की मौजूदगी तेजी से बढ़ी है। निजी हों अथवा सरकारी कंपनियां, महिलाओं को हिस्सेदारी 29 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। एकल स्वामित्व वाली कंपनियों में भी यह आंकड़ा 28 प्रतिशत है। तुलनात्मक रूप से महिला प्रतिनिधित्व के मामले में निजी कंपनियां आगे हैं। सरकारी कंपनियों में यह आंकड़ा 21 प्रतिशत, जबकि निजी कंपनियों में 30 प्रतिशत है। इस बदलाव के पीछे कानूनी अनिवार्यताओं को प्रमुख कारण माना गया है। भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा एक निश्चित टर्नओवर वाली सार्वजनिक कंपनियों के बोर्ड में कम-से-कम एक महिला निदेशक का होना अनिवार्य किया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने भी इस प्रावधान को कड़ाई से लागू किया है। इसके साथ ही कंपनियों का नजरिया बदलना भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा है कि बोर्डरूम में विविधता से न केवल सामाजिक सुधार होता है, बल्कि व्यवसाय को भी लाभ पहुंचता है। निवेशकों का दबाव भी इस परिवर्तन का एक उल्लेखनीय पहलू रहा है। आज वैश्विक निवेशक उन कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जो



गवर्नेंस। मानकों का पालन करती हैं। इन मानकों के प्रत्येकन में महिलाओं को भागीदारी एक महत्वपूर्ण पैमाना मानी जाती है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं में उच्च शिक्षा और पेशेवर दक्षता बढ़ने से भी नेतृत्व के पदों के लिए उनका दायरा विस्तृत हुआ है। बोर्डरूम में महिलाओं की उपस्थिति के लाभ भी कम नहीं हैं। महिलाएं अलग दृष्टिकोण, बेहतर जेखिम प्रबंधन क्षमता तथा नवीन समाधान लेकर आती हैं, जिससे निर्णय अधिक संतुलित और प्रभावी बनते हैं। विभिन्न शोधों के अनुसार महिला निदेशक बेहतर निगरानी, अधिक नैतिक संवेदनशीलता तथा बोर्ड की विचार-विमर्श प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। महिला नेतृत्व कार्यस्थल पर अधिक समावेशी वातावरण का निर्माण करता है, जिससे महिला कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे लंबे समय तक संस्थान से जुड़ी रहती हैं। इससे प्रतिभाशाली मानव संसाधन का दायरा बढ़ता है, जो कुशल प्रबंधन और बेहतर निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होता है। मैकिंसे और क्रेडिट सुइस सहित अनेक

अध्ययनों में यह सामने आया है कि जिन कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की संख्या अधिक होती है, उनका वित्तीय प्रदर्शन अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर रहता है। कॉर्पोरेट बोर्डरूम में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लैंगिक समानता, बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आर्थिक विकास की दिशा में निस्संदेह एक सकारात्मक परिवर्तन है। किंतु भारत में शीर्ष पदों तक पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या अभी भी काफी कम है। बोर्ड में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने के बावजूद, उच्चतम कार्यकारी पदों पर यह संख्या नाटकीय रूप से घट जाती है। लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, कारोबार के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में केवल नौ महिलाएं ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर कार्यरत हैं। मंत्रालय के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 में ऐसी कोई बरिभाषा न होने के कारण वह महिला अध्यक्षों अथवा मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारियों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखता। ये आंकड़े बोर्ड में प्रतिनिधित्व और सार्वोच्च कार्यकारी पदों पर उपस्थिति के बीच मौजूद बड़े अंतर

को उजागर करते हैं। वास्तव में, कुछ कंपनियों केवल औपचारिकता निभाने के लिए महिलाओं को बोर्ड में शामिल तो कर लेती हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक निर्णय-प्रक्रिया से दूर ही रखा जाता है। कई बार पारिवारिक व्यवसायों में परिवार की किसी महिला सदस्य को बिना पर्याप्त कॉर्पोरेट अनुभव के बोर्ड में शामिल कर केवल ख़ातापूर्ति कर दी जाती है। एक अन्य बड़ा कारण हमारा सामाजिक ढांचा भी है, जहां घरेलू दायित्वों का बोझ आज भी मुख्य रूप से महिलाओं पर ही रहता है। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में घरेलू कार्यों और देखभाल संबंधी गतिविधियों पर कहीं अधिक समय व्यतीत करती हैं। इसका सीधा प्रभाव उनके करियर की निरंतरता तथा वरिष्ठ पदों तक पहुंचने की संभावनाओं पर पड़ता है। मध्यम प्रबंधन स्तर पर करियर केक या पारिवारिक कारणाों से नौकरी छोड़ने की स्थिति भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या को सीमित कर देती है। कुल मिलाकर पारिवारिक जिम्मेदारियां, कार्यस्थल पर असुरक्षा, मातृत्व के बाद पुनः कार्यक्षेत्र में वापसी की चुनौतियां तथा पुरुष-प्रधान पेशेवर नेटवर्क जैसी बाधाएं आज भी महिलाओं के करियर विकास में बड़ी रुकावट बनी हुई हैं। बदलाव को यह आहट निस्संदेह सुखद है, किंतु वास्तविक लक्ष्य शीर्ष स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी को केवल एक अनिवार्य सदस्य तक सीमित रखने के बजाय 30 से 50 प्रतिशत तक पहुंचना होना चाहिए। यह तभी संभव है जब लैंगिक भेदभाव और सामाजिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर महिलाओं को समुचित अवसर और सहयोग प्रदान किया जाए।

अधिकारों का एक पड़ाव उत्तर भारत में प्रदेश हित में इबारत लिख गया। किशाऊ बांध परियोजना के बहाने सामने खड़ी सारी संभावनाएं अगर हिमाचल को सशक्त कर रही हैं, तो यह संघर्ष वर्तमान सुखबू सरकार को पुरस्कृत कर रहा है। उत्तराखंड-हिमाचल की सीमा पर 422 मेगावाट की इस परियोजना के मार्फत हिमाचल ने पहली बार अपने आर्थिक ताले खोले हैं। पहली बार हिमाचल की जल क्षमता को मोल तय हुआ है। कुल 15624 करोड़ की योजना में हिमाचल पार्टनर तो बना, लेकिन बिना धेला खर्चें यह इससे निकलते लाभों की भागीदारी में सुनिश्चित हुआ। अब सरकार का अनुमान है कि परियोजना के पूर्ण होते ही राज्य को 1200 करोड़ का सीधा मुनाफा मिलेगा। किशाऊ परियोजना के लिख गया। किशाऊ बांध परियोजना समझौते से बंधे दिल्ली, राजस्थान, उत्तर के बहाने सामने खड़ी सारी संभावनाएं अगर हिमाचल को वर्तमान सुखबू सरकार को पुरस्कृत अवसर भी हैं। जाहिर है हिमाचल सरकार के कर प्रशा है। उत्तराखंड-हिमाचल की प्रयास उस मुहाने पर खड़े हैं, जहां आगे चल कर केंद्रीय उपक्रमों द्वारा अर्जित विद्युत उत्पादन में बराबर को हिस्सेदारी तथा शानन परियोजना की मिलकीयत में पूरा हक हासिल होने की संभावना बढ़ी है। जल संसाधन हैं। पहली बार हिमाचल की जल हिमाचल का सामथ्र्य व आर्थिक विश्वास है और इसी नजरिए से हमने किशाऊ बांध परियोजना को अधिकारों का मानक पन दिया। इसी तर्ज पर 68 फीसदी जगह को जंगलात के अधीन करने वाले राज्य को धेला खर्चें यह इससे निकलते लाभों पर्यावरणीय हर्जाना चाहिए। जंगल में हिमाचल के अधिकार और स्वाभिमान छुपा है। विडंबना यह रही कि पहले विशेष दर्जा हासिल यह प्रदेश आरडीजी के तहत अपनी आर्थिक और वित्तीय क्षति की कुछ हद तक सीमित करता था, लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था से हारमन किया जा चुका है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का पहला दायित्व शांता कुमार ने उस समय पूरा किया था, जब केंद्र से जल विद्युत उत्पादन की स्थिति इस बहाने पहाड़ के पानी का स्वाभिमव में राज्य को मुफ्त बिजली का प्रावधान हुआ। तय किया है। यह पर्वतीय पानी की यह दूसरा अवसर है जब कोई मुख्यमंत्री हिमाचल के अधिकारों के तर्क पर आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन रहा है। हम इसे आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन का नारा मान अवसर भी है। जाहिर है हिमाचल सरकारें हैं। दरअसल पंजाब/पुर्नाटन में तय हुए, सरकार के प्रयास उस मुहाने पर खड़े हिमाचल के अधिकारों को हमने समझा ही है, जहां आगे चल कर केंद्रीय उपक्रमों द्वारा अर्जित विद्युत उत्पादन में बराबर की हिस्सेदारी तथा शानन हासिल होने की संभावना बढ़ी है। जल संसाधन हिमाचल का सामथ्र्य व आर्थिक विश्वास है और इसी नजरिए से हमने किशाऊ बांध परियोजना को अधिकारों का मानक बना दिया। इसी तर्ज पर 68 फीसदी जगह को जंगलात के अधीन करने वाले राज्य को धेला खर्चें यह इससे निकलते लाभों पर्यावरणीय हर्जाना चाहिए। जंगल में हिमाचल के अधिकार और स्वाभिमान छुपा है। विडंबना यह रही कि पहले विशेष दर्जा हासिल यह प्रदेश आरडीजी के तहत अपनी आर्थिक और वित्तीय क्षति की कुछ हद तक सीमित करता था, लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था से हारमन किया जा चुका है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का पहला दायित्व शांता कुमार ने उस समय पूरा किया था, जब केंद्र से जल विद्युत उत्पादन की स्थिति इस बहाने पहाड़ के पानी का स्वाभिमव में राज्य को मुफ्त बिजली का प्रावधान हुआ। तय किया है। यह पर्वतीय पानी की यह दूसरा अवसर है जब कोई मुख्यमंत्री हिमाचल के अधिकारों के तर्क पर आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन रहा है। हम इसे आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन का नारा मान अवसर भी है। जाहिर है हिमाचल सरकारें हैं। दरअसल पंजाब/पुर्नाटन में तय हुए, सरकार के प्रयास उस मुहाने पर खड़े हिमाचल के अधिकारों को हमने समझा ही है, जहां आगे चल कर केंद्रीय उपक्रमों द्वारा अर्जित विद्युत उत्पादन में बराबर की हिस्सेदारी तथा शानन हासिल होने की संभावना बढ़ी है। जल संसाधन हिमाचल का सामथ्र्य व आर्थिक विश्वास है और इसी नजरिए से हमने किशाऊ बांध परियोजना को अधिकारों का मानक बना दिया। इसी तर्ज पर 68 फीसदी जगह को जंगलात के अधीन करने वाले राज्य को धेला खर्चें यह इससे निकलते लाभों पर्यावरणीय हर्जाना चाहिए। जंगल में हिमाचल के अधिकार और स्वाभिमान छुपा है। विडंबना यह रही कि पहले विशेष दर्जा हासिल यह प्रदेश आरडीजी के तहत अपनी आर्थिक और वित्तीय क्षति की कुछ हद तक सीमित करता था, लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था से हारमन किया जा चुका है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का पहला दायित्व शांता कुमार ने उस समय पूरा किया था, जब केंद्र से जल विद्युत उत्पादन की स्थिति इस बहाने पहाड़ के पानी का स्वाभिमव में राज्य को मुफ्त बिजली का प्रावधान हुआ। तय किया है। यह पर्वतीय पानी की यह दूसरा अवसर है जब कोई मुख्यमंत्री हिमाचल के अधिकारों के तर्क पर आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन रहा है। हम इसे आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन का नारा मान अवसर भी है। जाहिर है हिमाचल सरकारें हैं। दरअसल पंजाब/पुर्नाटन में तय हुए, सरकार के प्रयास उस मुहाने पर खड़े हिमाचल के अधिकारों को हमने समझा ही है, जहां आगे चल कर केंद्रीय उपक्रमों द्वारा अर्जित विद्युत उत्पादन में बराबर की हिस्सेदारी तथा शानन हासिल होने की संभावना बढ़ी है। जल संसाधन हिमाचल का सामथ्र्य व आर्थिक विश्वास है और इसी नजरिए से हमने किशाऊ बांध परियोजना को अधिकारों का मानक बना दिया। इसी तर्ज पर 68 फीसदी जगह को जंगलात के अधीन करने वाले राज्य को धेला खर्चें यह इससे निकलते लाभों पर्यावरणीय हर्जाना चाहिए। जंगल में हिमाचल के अधिकार और स्वाभिमान छुपा है। विडंबना यह रही कि पहले विशेष दर्जा हासिल यह प्रदेश आरडीजी के तहत अपनी आर्थिक और वित्तीय क्षति की कुछ हद तक सीमित करता था, लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था से हारमन किया जा चुका है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का पहला दायित्व शांता कुमार ने उस समय पूरा किया था, जब केंद्र से जल विद्युत उत्पादन की स्थिति इस बहाने पहाड़ के पानी का स्वाभिमव में राज्य को मुफ्त बिजली का प्रावधान हुआ। तय किया है। यह पर्वतीय पानी की यह दूसरा अवसर है जब कोई मुख्यमंत्री हिमाचल के अधिकारों के तर्क पर आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन रहा है। हम इसे आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन का नारा मान अवसर भी है। जाहिर है हिमाचल सरकारें हैं। दरअसल पंजाब/पुर्नाटन में तय हुए, सरकार के प्रयास उस मुहाने पर खड़े हिमाचल के अधिकारों को हमने समझा ही है, जहां आगे चल कर केंद्रीय उपक्रमों द्वारा अर्जित विद्युत उत्पादन में बराबर की हिस्सेदारी तथा शानन हासिल होने की संभावना बढ़ी है। जल संसाधन हिमाचल का सामथ्र्य व आर्थिक विश्वास है और इसी नजरिए से हमने किशाऊ बांध परियोजना को अधिकारों का मानक बना दिया। इसी तर्ज पर 68 फीसदी जगह को जंगलात के अधीन करने वाले राज्य को धेला खर्चें यह इससे निकलते लाभों पर्यावरणीय हर्जाना चाहिए। जंगल में हिमाचल के अधिकार और स्वाभिमान छुपा है। विडंबना यह रही कि पहले विशेष दर्जा हासिल यह प्रदेश आरडीजी के तहत अपनी आर्थिक और वित्तीय क्षति की कुछ हद तक सीमित करता था, लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था से हारमन किया जा चुका है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का पहला दायित्व शांता कुमार ने उस समय पूरा किया था, जब केंद्र से जल विद्युत उत्पादन की स्थिति इस बहाने पहाड़ के पानी का स्वाभिमव में राज्य को मुफ्त बिजली का प्रावधान हुआ। तय किया है। यह पर्वतीय पानी की यह दूसरा अवसर है जब कोई मुख्यमंत्री हिमाचल के अधिकारों के तर्क पर आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन रहा है। हम इसे आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन का नारा मान अवसर भी है। जाहिर है हिमाचल सरकारें हैं। दरअसल पंजाब/पुर्नाटन में तय हुए, सरकार के प्रयास उस मुहाने पर खड़े हिमाचल के अधिकारों को हमने समझा ही है, जहां आगे चल कर केंद्रीय उपक्रमों द्वारा अर्जित विद्युत उत्पादन में बराबर की हिस्सेदारी तथा शानन हासिल होने की संभावना बढ़ी है। जल संसाधन हिमाचल का सामथ्र्य व आर्थिक विश्वास है और इसी नजरिए से हमने किशाऊ बांध परियोजना को अधिकारों का मानक बना दिया। इसी तर्ज पर 68 फीसदी जगह को जंगलात के अधीन करने वाले राज्य को धेला खर्चें यह इससे निकलते लाभों पर्यावरणीय हर्जाना चाहिए। जंगल में हिमाचल के अधिकार और स्वाभिमान छुपा है। विडंबना यह रही कि पहले विशेष दर्जा हासिल यह प्रदेश आरडीजी के तहत अपनी आर्थिक और वित्तीय क्षति की कुछ हद तक सीमित करता था, लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था से हारमन किया जा चुका है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का पहला दायित्व शांता कुमार ने उस समय पूरा किया था, जब केंद्र से जल विद्युत उत्पादन की स्थिति इस बहाने पहाड़ के पानी का स्वाभिमव में राज्य को मुफ्त बिजली का प्रावधान हुआ। तय किया है। यह पर्वतीय पानी की यह दूसरा अवसर है जब कोई मुख्यमंत्री हिमाचल के अधिकारों के तर्क पर आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन रहा है। हम इसे आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन का नारा मान अवसर भी है। जाहिर है हिमाचल सरकारें हैं। दरअसल पंजाब/पुर्नाटन में तय हुए, सरकार के प्रयास उस मुहाने पर खड़े हिमाचल के अधिकारों को हमने समझा ही है, जहां आगे चल कर केंद्रीय उपक्रमों द्वारा अर्जित विद्युत उत्पादन में बराबर की हिस्सेदारी तथा शानन हासिल होने की संभावना बढ़ी है। जल संसाधन हिमाचल का सामथ्र्य व आर्थिक विश्वास है और इसी नजरिए से हमने किशाऊ बांध परियोजना को अधिकारों का मानक बना दिया। इसी तर्ज पर 68 फीसदी जगह को जंगलात के अधीन करने वाले राज्य को धेला खर्चें यह इससे निकलते लाभों पर्यावरणीय हर्जाना चाहिए। जंगल में हिमाचल के अधिकार और स्वाभिमान छुपा है। विडंबना यह रही कि पहले विशेष दर्जा हासिल यह प्रदेश आरडीजी के तहत अपनी आर्थिक और वित्तीय क्षति की कुछ हद तक सीमित करता था, लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था से हारमन किया जा चुका है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का पहला दायित्व शांता कुमार ने उस समय पूरा किया था, जब केंद्र से जल विद्युत उत्पादन की स्थिति इस बहाने पहाड़ के पानी का स्वाभिमव में राज्य को मुफ्त बिजली का प्रावधान हुआ। तय किया है। यह पर्वतीय पानी की यह दूसरा अवसर है जब कोई मुख्यमंत्री हिमाचल के अधिकारों के तर्क पर आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन रहा है। हम इसे आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन का नारा मान अवसर भी है। जाहिर है हिमाचल सरकारें हैं। दरअसल पंजाब/पुर्नाटन में तय हुए, सरकार के प्रयास उस मुहाने पर खड़े हिमाचल के अधिकारों को हमने समझा ही है, जहां आगे चल कर केंद्रीय उपक्रमों द्वारा अर्जित विद्युत उत्पादन में बराबर की हिस्सेदारी तथा शानन हासिल होने की संभावना बढ़ी है। जल संसाधन हिमाचल का सामथ्र्य व आर्थिक विश्वास है और इसी नजरिए से हमने किशाऊ बांध परियोजना को अधिकारों का मानक बना दिया। इसी तर्ज पर 68 फीसदी जगह को जंगलात के अधीन करने वाले राज्य को धेला खर्चें यह इससे निकलते लाभों पर्यावरणीय हर्जाना चाहिए। जंगल में हिमाचल के अधिकार और स्वाभिमान छुपा है। विडंबना यह रही कि पहले विशेष दर्जा हासिल यह प्रदेश आरडीजी के तहत अपनी आर्थिक और वित्तीय क्षति की कुछ हद तक सीमित करता था, लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था से हारमन किया जा चुका है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का पहला दायित्व शांता कुमार ने उस समय पूरा किया था, जब केंद्र से जल विद्युत उत्पादन की स्थिति इस बहाने पहाड़ के पानी का स्वाभिमव में राज्य को मुफ्त बिजली का प्रावधान हुआ। तय किया है। यह पर्वतीय पानी की यह दूसरा अवसर है जब कोई मुख्यमंत्री हिमाचल के अधिकारों के तर्क पर आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन रहा है। हम इसे आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन का नारा मान अवसर भी है। जाहिर है हिमाचल सरकारें हैं। दरअसल पंजाब/पुर्नाटन में तय हुए, सरकार के प्रयास उस मुहाने पर खड़े हिमाचल के अधिकारों को हमने समझा ही है, जहां आगे चल कर केंद्रीय उपक्रमों द्वारा अर्जित विद्युत उत्पादन में बराबर की हिस्सेदारी तथा शानन हासिल होने की संभावना बढ़ी है। जल संसाधन हिमाचल का सामथ्र्य व आर्थिक विश्वास है और इसी नजरिए से हमने किशाऊ बांध परियोजना को अधिकारों का मानक बना दिया। इसी तर्ज पर 68 फीसदी जगह को जंगलात के अधीन करने वाले राज्य को धेला खर्चें यह इससे निकलते लाभों पर्यावरणीय हर्जाना चाहिए। जंगल में हिमाचल के अधिकार और स्वाभिमान छुपा है। विडंबना यह रही कि पहले विशेष दर्जा हासिल यह प्रदेश आरडीजी के तहत अपनी आर्थिक और वित्तीय क्षति की कुछ हद तक सीमित करता था, लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था से हारमन किया जा चुका है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का पहला दायित्व शांता कुमार ने उस समय पूरा किया था, जब केंद्र से जल विद्युत उत्पादन की स्थिति इस बहाने पहाड़ के पानी का स्वाभिमव में राज्य को मुफ्त बिजली का प्रावधान हुआ। तय किया है। यह पर्वतीय पानी की यह दूसरा अवसर है जब कोई मुख्यमंत्री हिमाचल के अधिकारों के तर्क पर आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन रहा है। हम इसे आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन का नारा मान अवसर भी है। जाहिर है हिमाचल सरकारें हैं। दरअसल पंजाब/पुर्नाटन में तय हुए, सरकार के प्रयास उस मुहाने पर खड़े हिमाचल के अधिकारों को हमने समझा ही है, जहां आगे चल कर केंद्रीय उपक्रमों द्वारा अर्जित विद्युत उत्पादन में बराबर की हिस्सेदारी तथा शानन हासिल होने की संभावना बढ़ी है। जल संसाधन हिमाचल का सामथ्र्य व आर्थिक विश्वास है और इसी नजरिए से हमने किशाऊ बांध परियोजना को अधिकारों का मानक बना दिया। इसी तर्ज पर 68 फीसदी जगह को जंगलात के अधीन करने वाले राज्य को धेला खर्चें यह इससे निकलते लाभों पर्यावरणीय हर्जाना चाहिए। जंगल में हिमाचल के अधिकार और स्वाभिमान छुपा है। विडंबना यह रही कि पहले विशेष दर्जा हासिल यह प्रदेश आरडीजी के तहत अपनी आर्थिक और वित्तीय क्षति की कुछ हद तक सीमित करता था, लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था से हारमन किया जा चुका है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का पहला दायित्व शांता कुमार ने उस समय पूरा किया था, जब केंद्र से जल विद्युत उत्पादन की स्थिति इस



उन्होंने कहा, वह एक शानदार प्रतिस्पर्धी, लीडर और ऊँचे मानक तय करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। खेल के सर्वोच्च स्तर पर उनका अनुभव हमारे खिलाड़ियों के लिए बेहद मूल्यवान रहा है। बीमूस ने कहा, मैट ने हरिकेंस को बहुत कुछ दिया है और क्लब के लिए उनके योगदान के लिए हम बेहद आभारी हैं।



पीएम मोदी के जन्मदिन पर जरूरतमंदों में भोजन वितरित



हैदराबाद, 17 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, तेलंगाना की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण

के आसपास जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया गया। आयोजन के माध्यम से सेवा, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। इस पहल में लोगों ने एक साथ आकर जरूरतमंदों के साथ भोजन साझा किया और मानवता एवं दया की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की गई।

कार्यक्रम में भाजपा तेलंगाना अध्यक्ष सरदार जगमोहन सिंह के साथ हर्षोत्तम सिंह गुलाटी, रजनीश जैन, गजनी जी, गुरचरण सिंह, अवाइस मिर्जा, रिदा कुदूस, फरनाज, नसीर, समी खान, रहमतुल्ला, दिनेश, सुमीत, रंजीत सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।

सेवा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को भोजन परोसा गया।

स्कूल फॉर द ब्लाइंड तथा अफजलंग गुरुद्वारा एवं मस्जिद

‘राजाधिराज यात्रा – कृष्ण लीला आपके द्वार’ का आयोजन 2 अक्टूबर से

शिल्पकला वेदिका में मंचित होगा भगवान श्री कृष्ण की अमर गाथाओं और लीलाओं को समर्पित भव्य नाट्य मंचन



हैदराबाद, 17 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

धरराज नाथवाणी की परिकल्पना से सजे भव्य नाट्य मंचन ‘राजाधिराज यात्रा – कृष्ण लीला आपके द्वार’ के हैदराबाद संस्करण का भव्य अनावरण 17 सितंबर को बेमामेट स्थित होटल प्लाजा में एक कर्टन रेज़र कार्यक्रम के दौरान किया गया। भगवान श्री कृष्ण की कालातीत लीलाओं पर आधारित इस दिव्य शो का आयोजन 2 से 4 अक्टूबर 2026 तक हायटेक सिटी स्थित ‘शिल्पकला वेदिका’ में किया जाएगा। तीन दिवसीय इस आयोजन में 10,000 से अधिक दर्शकों के जुटने की संभावना है। इस भव्य शो को हैदराबाद में ‘राग रंग रास’ द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी स्थापना रितु शाह और रोमित शाह ने की है।

संस्थापकों ने बताया कि हैदराबाद में इतने बड़े पैमाने का सांस्कृतिक अनुभव लाना उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर ‘राग रंग रास’ की संस्थापिका रितु शाह ने कहा,

“राजाधिराज एक अनूठा नाट्य अनुभव है जो संगीत, नृत्य और द्रव्य कला के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीलाओं को जीवंत करता है।

हैदराबाद की जनता कला और संस्कृति का सम्मान करती है, इसलिए हम इस अद्भुत प्रस्तुति को यहां ला रहे हैं।” वहीं संस्थापक रोमित शाह ने कहा कि देश भर में मिल रहे शानदार प्रतिसाद के बाद हैदराबाद के दर्शकों के लिए श्री कृष्ण की कालातीत यात्रा को नए अंदाज में अनुभव कराने का यह एक बेहतरीन अवसर है।

यह महानाट्य अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली और दुबई में अब तक 33 हाउसफुल शो कर चुका है, जिसे 37,000 से अधिक दर्शक देख चुके हैं।

120 से अधिक कलाकारों व तकनीशियनों के दल, 500 से अधिक विशेष परिधानों और 20 मूल गीतों से सजी यह भव्य प्रस्तुति धरराज नाथवाणी द्वारा परिकल्पित है।

जैन आराधना भवन में अठाई तपस्वियों का बहुमान



हैदराबाद, 17 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। जैन रत्न रमेश पी. तातेड की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जैन आराधना भवन, रसूलपुरा में अठाई तपस्या करने वाले हर्ष भंडारी, मेघा भंडारी एवं स्पर्श भंडारी का श्रद्धा एवं उत्साह के साथ बहुमान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में

समाजजन उपस्थित रहे।

भंडारी परिवार की ओर से रोहिणी देवी-प्रकाशमल भंडारी, ज्योत्सना-अविनाश भंडारी, प्राप्ति-विक्रम भंडारी, देविता-विशाल भंडारी एवं समस्त भंडारी परिवार, लालवानी परिवार, कमलादेवी-बाबूलालजी संकलेचा (रासोनी परिवार),

रमेश पी. तातेड सिरौही परिवार तथा सभी गणमान्य सदस्यों द्वारा तपस्वियों का बहुमान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी समाजजनों के लिए स्नेहपूर्वक भोजन की व्यवस्था भी की गई। इसी अवसर पर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए श्री तीर्थसुंदरविजयजी म.सा. आदि ठाणा का रसूलपुरा में आगमन हुआ।

उनके सान्निध्य में धार्मिक वातावरण बना रहा।

कार्यक्रम के दौरान प्रीतिन परमार के खीर समुद्र तप का पारणा भी संपन्न हुआ। वहीं, सकल संघ की नवकारसी का लाभ लीलाबेन बाबूलालजी परमार, मीना-मनीष एवं सोनल-प्रीतिन ने लिया।

सेवा का भाव मन से आता है : सुभाष अग्रवाल



मानव सेवा है।

कार्यक्रम में मनीष अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, भंवरलाल गुप्ता तथा जयप्रकाश सारड़ सहित राधे-राधे ग्रुप के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने सेवा कार्य में सहयोग करते हुए नियमित अन्नदान कार्यक्रम को सफल बनाया।

हैदराबाद। राधे-राधे ग्रुप हैदराबाद के तत्वावधान में इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल के पास स्थित केबीआर पार्क के वॉटर टैंक पर गुरुवार को नियमित अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों को भोजन वितरित कर मानव सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाया गया। ग्रुप के सदस्यों ने सेवा कार्य में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए समाज में सेवा, सहयोग और संवेदना का संदेश दिया।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सुभाष अग्रवाल ने कहा कि सेवा का भाव मन से आता है। जब मन में दूसरों की सहायता करने की भावना जागृत होती है, तो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि सेवा केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना और उसके जीवन में थोड़ी राहत पहुंचाना भी सच्ची



प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद में हिंदी पखवाड़ा का भव्य शुभारंभ



समारोह के दौरान सर्वप्रथम माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के संदेश का ऑनलाइन प्रसारण किया गया, जिसमें राजभाषा के महत्व और राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात एसपीएमसीआईएल के आदरणीय सीएमडी श्री विजय रंजन सिंह जी के संदेश का वाचन किया गया, जिसमें उन्होंने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी को अपनाने और इसके प्रयोग को अधिक सहज बनाने का आह्वान

किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपर महाप्रबंधक (मा.सं.) श्री दुर्गा प्रसाद और महासचिव, एचएसपीपीईशू श्री रविकांत रेड्डी जी ने भी सभा को संबोधित किया और पखवाड़े के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

अपने मुख्य संबोधन में मुख्य महाप्रबंधक महोदय ने सभी को बधाई देते हुए ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने का विशेष उल्लेख किया और कहा कि जिस तरह इस राष्ट्रीय गीत ने पूरे देश को जोड़ा था, वैसे ही हिंदी भाषा

भी हम सबको एक साथ जोड़ती है। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों, फाइलों और ई-मेल में हिंदी का इस्तेमाल शुरू करने का आग्रह किया।

उन्होंने यह भी अपील की कि हिंदी का प्रयोग केवल इस पखवाड़े तक सीमित न रहे, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के काम का अभिन्न हिस्सा बने।

अंत में श्री संतोष साव, पर्यवेक्षक (राजभाषा) द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ इस उद्घाटन सत्र का सफलतापूर्वक समापन हुआ।

हैदराबाद मुक्ति दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी ‘वंदे मातरम्’ रामचंद्र राव को दी गई श्रद्धांजलि



हैदराबाद, 17 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। हैदराबाद मुक्ति दिवस के पावन अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री ‘वंदे मातरम्’ रामचंद्र राव के अमूल्य योगदान और बलिदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उल्लेखनीय है कि 17 सितंबर 1948 को ही हैदराबाद भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना था।

इस ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी ने स्वर्गीय ‘वंदे मातरम्’ रामचंद्र राव के सुपुत्र श्री आदित्य जी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ विशेष मुलाकात की। 78वें हैदराबाद मुक्ति दिवस के इस विशेष अवसर पर हैदराबाद को भारत में एकीकृत करने और स्वतंत्रता की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शूरवीरों व स्वतंत्रता सेनानियों के अभूतपूर्व त्याग को आदरपूर्वक नमन किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर भाजपा गोलकुंडा जिला अध्यक्ष श्री उमा महेंद्र जी, लाल सिंह जी, श्रीराम व्यास जी, सुरेंद्र जी, नटराज नामधारी जी, विपिन जी, आला पुरुषोत्तम जी, राहुल जी, सुरेश जोशी जी, जयपाल सिंह जी, रामू जी, श्रीकांत जी, महेश मयाद्री जी, अमरदीप सिंह जी, विष्णु वणकर जी, रोहित जोहरी जी, कुणाल जी, सुमन जी, कैलाश जी सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

लेजेंड वेंकटेश, नारायणगुड़ा, हैदराबाद अपार्टमेंट की

निवासी महिलाओं ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर गायत्री लाहोटी, मंजू चोरडिया, शोभा भराडिया, अनुराधा, अरुणा अग्रवाल, नेहा पालन, रमा काकुमनी, निर्मला लाहोटी, सुंदर भराडिया, विभा विजयवर्गी एवं दुर्गा राठी उपस्थित रहीं।



श्री मारुति परिवार की ओर से गणेशोत्सव के अवसर पर दुर्गा निकेतन का राजा गणेश पंडाल, दुर्गा निकेतन, मंगलहाट में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा एवं आरती में भाग लिया और श्रद्धा व भक्ति के साथ आनंद लिया।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

एक थी...

अंतिम फैसला बाद में, उपचुनावों पर तत्काल असर चुनाव आयोग ने इस पूरे विवाद के अंतिम और ठोस निपटारे के लिए दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दावों की जांच की प्रक्रिया शुरू की है। आयोग के सामने मुख्य सवाल पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण, नाम और आक्षेपित चुनाव चिह्न के अधिकार से जुड़ा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार आयोग ने तत्काल अंतिम फैसला देने के बजाय दोनों पक्षों से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे थे और उपचुनावों की नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए अंतर्गम व्यवस्था पर विचार किया था।

यदि आयोग दोनों पक्षों को मूल पार्टी के नाम और आक्षेपित चुनाव चिह्न के इस्तेमाल से रोकने की अंतर्गम व्यवस्था करता है, तो दोनों गुटों को अलग नाम और अधिसूचित स्वतंत्र चुनाव चिह्नों के विकल्प देने पड़ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य अंतिम विवाद का फैसला होने तक दोनों पक्षों को चुनावी प्रक्रिया में अलग पहचान उपलब्ध कराना होगा। इस तरह की प्रक्रिया चुनाव आयोग पहले भी पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़े विवादों में अपना चुका है।

बंडी-रेवंत...

मुद्दों पर दिखाई देने वाली समानता को लेकर भी चर्चाएं हैं। वहीं भाजपा समर्थक पक्ष का तर्क है कि बीआरएस शासन से जुड़े कथित भूमि और भ्रष्टाचार के मामलों को उठाना कांग्रेस के समर्थन के समान नहीं माना जा सकता।

कांग्रेस सरकार से जुड़े कथित घोटालों और लंबे समय से ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के मामलों पर भी भाजपा के कुछ विधायक सवाल उठा चुके हैं। इन मुद्दों पर बंडी संजय की प्रतिक्रिया को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं।

बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ से जुड़े पुराने पोस्को मामले का राजनीतिक संदर्भ में उल्लेख करते हुए भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे संवेदनशील मामले में

किसी भी राजनीतिक निष्कर्ष से पहले न्यायिक रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयानों को आधार बनाना जरूरी है।

अब असली सवाल यही है कि तेलंगाना भाजपा की राजनीतिक रणनीति का केंद्र कांग्रेस सरकार के खिलाफ सीधा संघर्ष होगा या बीआरएस के खिलाफ अभियान ? संजय के आगामी बयानों और पार्टी के अगले राजनीतिक कार्यक्रमों से इस दिशा की तस्वीर और स्पष्ट होने की संभावना है।

‘सिलेंडर महिला’ ...

इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि महिलाएं दिन-रात अपने घरों में खुद गैस सिलेंडर उठाती और बदलती हैं। अदालत ने इस मामले में नौकरी के बजाय मुआवजा दिए जाने के मुद्दे पर कहा कि याचिकाकर्ता महिला अब सेवानिवृत्ति की उम्र पार कर चुकी हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस पड़ाव पर नौकरी देने के बजाय एकमुश्त 12 लाख रुपये का मुआवजा देना उचित समझा।

बता दें कि सुमित्रा हरियाणा के गुड्डहा गांव की रहने वाली हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक भेदभाव के चलते इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में नौकरी से वंचित किए जाने के मामले में 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुमित्रा उन 49 लोगों में शामिल थीं, जिनकी सिफारिश उपायुक्त की अध्यक्षता वाली एक स्थानीय समिति ने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में रीफिलिंग हेल्पर या आकस्मिक खलासी के पद के लिए की थी। उन्हें केवल महिला होने के आधार पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे नारीत्व का अपमान बताया।

लंबी कानूनी लड़ाई और महिला के सेवानिवृत्ति की उम्र तक पहुंचने के कारण अदालत ने अब उन्हें नौकरी देने के बजाय 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

यूपीआई कस्टमर...

और पिछले वर्ष की समान अवधि के आंकड़ों से उनकी तुलना की जाएगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि नया शुल्क लागू होने के बाद यूपीआई लेन-देन और उसके उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। नए ढांचे के तहत 2,000 रुपये तक के व्यापारी भुगतान और छोटे कारोबारियों के लिए निर्धारित शुल्क-एमडीआर व्यवस्था वाले लेन-देन पर शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, करीब 96 प्रतिशत व्यापारी-आधारित यूपीआई लेन-देन इससे प्रभावित नहीं होंगे। व्यक्ति से व्यक्ति होने वाले सभी यूपीआई लेन-देन भी पूरी तरह निशुल्क रहेंगे।

18 प्रतिशत जीएसटी से राहत के उपाय पर भी विचार जीएसटी के दायरे से बाहर रहने वाले कारोबारियों को यूपीआई शुल्क पर लगने वाले 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर से राहत देने के उपायों पर भी विचार किया जा सकता है। इस मामले को जीएसटी परिषद की बैठक में लाया जा सकता है।

जीएसटी में पंजीकृत कारोबारी एमडीआर पर भुगतान किए गए 18 प्रतिशत जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकेंगे। हालांकि, ऐसे कारोबारी जो जीएसटी से मुक्त वस्तुओं या सेवाओं से जुड़े हैं, उनके लिए इस कर का प्रभाव अलग हो सकता है।

व्यापारी शुल्क ग्राहकों पर नहीं डाल पाएंगे

सरकारी सूत्रों का कहना है कि यूपीआई भुगतान पर शुल्क लागू होने के बाद नकदी से खरीदारी बढ़ने की संभावना नहीं है। सरकार का मानना है कि देश की अपनी मजबूत डिजिटल भुगतान व्यवस्था होनी चाहिए और इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है। एमडीआर के रूप में होने वाले संग्रह का पांच प्रतिशत यूपीआई नेटवर्क को मजबूत करने और छोटे कारोबारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य यूपीआई भुगतान की सुविधा को उन लोगों तक भी पहुंचाना है,

जो अभी इससे पूरी तरह नहीं जुड़े हैं।

अमेरिका के दबाव के दावे पर सरकार का अलग रुख सूत्रों के अनुसार, अमेरिका ने भारत से अपने देश की कंपनी के क्रेडिट कार्ड को यूपीआई भुगतान सुविधा से जोड़ने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका में जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान पर शुल्क लिया जाता है, जबकि भारत के अपने रुपे कार्ड को एमडीआर से मुक्त रखा गया है। इसका उद्देश्य रुपे कार्ड को देश में अधिक से अधिक लोगों के बीच प्रचलित करना बताया गया है।

नए एमडीआर ढांचे के तहत 2,000 रुपये से अधिक के पात्र व्यापारी भुगतान पर सामान्य दर 0.4 प्रतिशत होगी। इस शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति लेन-देन रखी गई है। 75,000 रुपये के भुगतान पर 300 रुपये की अधिकतम सीमा पूरी हो जाती है और इससे अधिक के लेन-देन पर भी अधिकतम एमडीआर 300 रुपये ही रहेगा।

क्या बदलेगा और क्या रहेगा मुफ्त

व्यक्ति से व्यक्ति होने वाला यूपीआई भुगतान किसी भी राशि पर मुफ्त रहेगा। 2,000 रुपये तक के व्यापारी भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए भी शुल्क-एमडीआर की व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार के अनुसार, नए शुल्क का दायरा चुनिंदा व्यापारी लेन-देन तक ही सीमित रहेगा।

जन्म-मृत्यु ...

यानी इस अवधि में केवल रजिस्ट्रार के स्तर पर आ-वेदन देकर पंजीकरण कराना संभव नहीं होगा। दो साल बाद अदालत की मंजूरी अनिवार्य यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के दो वर्ष से अधिक समय बाद दी जाती है, तो मामले का निपटारा केवल प्रशासनिक स्तर पर नहीं हो सकेगा। नए प्रावधान के अनुसार ऐसे पंजीकरण के लिए उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम गैणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट जन्म या मृत्यु की घटना की

सत्यता का सत्यापन करने के बाद ही पंजीकरण का आदेश दे सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होगा। मूल जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 में देरी से पंजीकरण के लिए पहले से प्रावधान मौजूद थे। पहले एक वर्ष से अधिक समय तक पंजीकरण नहीं होने पर प्रथम गैणी मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती थी। 2026 के संशोधन ने अब एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक की देरी के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर अलग व्यवस्था बनाई है, जबकि दो वर्ष से अधिक की देरी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की व्यवस्था की गई है।

क्यों किया गया कानून में बदलाव ?

नए प्रावधानों का उद्देश्य देर से होने वाले जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया में सत्यापन को मजबूत करना और रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ाना है। लंबे समय से लंबित या बहुत देर से किए जाने वाले पंजीकरण में अब संबंधित अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा घटना की वास्तविकता की जांच आवश्यक होगी। इससे जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। समय पर पंजीकरण कराने से नागरिकों को भविष्य में पहचान, सरकारी सेवाओं और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में दस्तावेज संबंधी परेशानी से भी बचाया जा सकता है।

1 अक्टूबर 2026 से नए प्रावधान लागू होने के बाद जन्म या मृत्यु का पंजीकरण समय पर कराना पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक वर्ष से अधिक की देरी होने पर प्रशासनिक अधिकारी के आदेश की जरूरत होगी, जबकि दो वर्ष से अधिक की देरी के मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसलिए जन्म और मृत्यु की घटना होने के बाद निर्धारित समय-सीमा में पंजीकरण कराना सबसे सरल प्रक्रिया रहेगी। देर होने पर अतिरिक्त सत्यापन, शुल्क और संबंधित अधिकारी या अदालत के आदेश की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।

BOOK YOUR DISPLAY CLASSIFIED ADVERTISEMENTS AT

Timings : 9 am to 7 pm

Head office

SHREE SIDDHIVINAYAK PUBLICATIONS,

Plot No. A-23/5 & 6 2nd Floor,

APIE, Balanagar, Hyderabad - 500 037

City office

SHREE SIDDHIVINAYAK PUBLICATIONS,

Plot No. A-23/5 & 6 2nd Floor,

APIE, Balanagar,

Hyderabad - 500 037

8688868345

शुभ लाभ

महारे

भाग्यनगर

दैनिक हिन्दी शुभ लाभ, हैदराबाद, शुक्रवार, 18 सितंबर, 2026

शुभ लाभ

आपकी सेवा में

शुभ लाभ से जुड़ी किसी भी समस्या या सुझाव के लिए

मो. 86888 68345 पर संपर्क करें ।

मास्टर सर्कुलर्स और सतर्कता मैनुअल 2026 पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

हैदराबाद, 18 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। एनएमडीसी लिमिटेड के सतर्कता विभाग ने 17 सितंबर 2026 को हैदराबाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा आयोजित मास्टर सर्कुलर्स और सतर्कता मैनुअल 2026 पर दक्षिण क्षेत्र के संगठनों के सतर्कता अधिकारियों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सह-मेजबानी की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, पूर्व विशेष निदेशक, सीबीआई द्वारा प्रतिभागियों से वर्चुवल रूप में संबोधित किया गया, जिन्होंने सीवीसी द्वारा जारी मास्टर परिपत्रों के महत्व और सतर्कता मैनुअल के संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मियों के रोटेशन के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो एक महत्वपूर्ण निवारक सतर्कता उपाय के रूप में सिद्ध है।

इस अवसर पर सीवीसी के सलाहकार श्री राजीव वर्मा, सीवीसी के निदेशक श्री अजय कुमार वर्मा और ओएसडी, सीवीसी श्री अरविंद कुमार के साथ-साथ सुश्री स्मृति रेड्डी, सीवीओ, मिथानी और बीडीएल; श्री पी. कृष्ण कुमार, सीवीओ, ईसीआईएल; और श्री सी. नीलकंठ रेड्डी, सीवीओ, एनएमडीसी लिमिटेड आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही।



सीवीसी के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने सतर्कता मैनुअल 2026 के संबंध में बहुत ही सार्थक जानकारी दी है, जिसमें समय समय पर लाए गए प्रमुख परिवर्तनों और सतर्कता प्रशासन के लिए उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने हाल ही में जारी किए गए सीवीसी के मास्टर सर्कुलर्स पर भी विस्तार से बताया, जिसमें उनके महत्वपूर्ण प्रावधान और व्यावहारिक प्रासंगिकता भी शामिल है। कार्यक्रम के पूरे सत्र अत्यधिक संवादात्मक

थे, जिसमें विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के प्रश्नों व संदेहों का समाधान किया और व्यावहारिक चर्चाओं के माध्यम से मूल्यवान स्पष्टीकरण प्रदान किए। इस कार्यक्रम में दक्षिण क्षेत्र के लगभग 75 सतर्कता अधिकारियों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सत्रों ने प्रतिभागियों की अद्यतन सतर्कता ढांचे की समझ को बढ़ाया और सतर्कता प्रथाओं में स्थिरता को बढ़ावा देने और संस्थागत

क्षमता को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान की। सीवीओ, एनएमडीसी ने सतर्कता अधिकारियों के लिए सीवीसी मास्टर परिपत्रों और सतर्कता मैनुअल 2026 के महत्व पर जोर दिया और साथ ही उन्होंने सतर्कता कार्यों में इन परिपत्रों और सतर्कता मैनुअल के प्रावधानों की पूरी समझ और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। सतर्कता के विभागाध्यक्ष ने सभी प्रतिष्ठित वक्ताओं को उनके बहुमूल्य ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए और प्रतिभागियों को उनकी उत्साही भागीदारी, ध्यानपूर्वक सुनने और उनकी सार्थक प्रतिभागिता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। इनकी प्रतिभागिता ने कार्यक्रम को अत्यधिक संवादात्मक और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कार्यक्रम पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और प्रभावी सतर्कता प्रशासन को विशेष महत्व देते हुए भाग लेने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए, अद्यतन सतर्कता मैनुअल और मास्टर सर्कुलर्स के विस्तृत प्रसार, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुआ। राष्ट्रांगन और राष्ट्रीय गीत के आलापन के साथ कार्यक्रम का समापन संपन्न हुआ।



संस्कारों से मिलता है सेवा का भाव : जगत नारायण अग्रवाल

हैदराबाद। राधे-राधे ग्रुप हैदराबाद के तत्वावधान में गुरुवार को बेगम बाजार स्थित भू देवी माता मंदिर के पास गौशाला के सामने नियमित अन्नदान एवं सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। सेवा कार्य में ग्रुप के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए मानव सेवा का संदेश दिया।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राधे-राधे ग्रुप हैदराबाद के संयोजक जगत नारायण अग्रवाल ने कहा कि सेवा का भाव संस्कारों से ही मिलता है। व्यक्ति के जीवन में संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका



होती है। परिवार से मिलने वाले सेवा, सहयोग और परोपकार के संस्कार ही आगे चलकर समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब

संस्कृति में अन्नदान को विशेष महत्व दिया गया है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराना केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि मानवता और संवेदना से जुड़ा पुण्य कार्य है। सेवा करते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जरूरतमंद की जरूरत को समझकर उसकी सहायता करना ही सच्ची सेवा है। कार्यक्रम में पन्नलाल अग्रवाल, अनिल अग्रवाल धरसुवाले सहित राधे-राधे ग्रुप हैदराबाद के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने सेवा कार्य में सहयोग करते हुए अन्नदान कार्यक्रम को सफल बनाया।

सिखवाल ब्राह्मण समाज की बैठक संपन्न



हैदराबाद, 17 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। सिखवाल ब्राह्मण समाज (पंजीकृत संस्था) की एक महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष भगवान व्यास की अध्यक्षता में श्रृंगी ऋषि भवन में आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ श्रृंगी ऋषि की वंदना के साथ हुआ।

महामंत्री श्यामसुंदर तिवारी ने बताया कि संस्था द्वारा विगत 29 वर्षों से गणेश विसर्जन के अवसर पर आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद एवं जल की व्यवस्था लाल बहादुर स्टेडियम, बशीरबाग में भव्य पंडाल लगाकर की जाती

रही है। इस वर्ष 30वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रसाद एवं जल वितरण कार्यक्रम 24 सितंबर 2026, गुरुवार रात 9 बजे से 25 सितंबर 2026, शुक्रवार मध्यरात्रि तक अनवरत जारी रहेगा। बैठक में इस आयोजन को लेकर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

बैठक में संस्था के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वर्तमान में संस्था के 65 सदस्यों की संख्या को एक माह के भीतर बढ़ाकर 100 करने और इसके बाद नई कार्यकारिणी का चुनाव कराने का निर्णय

लिया गया। इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि एक व्यक्ति अध्यक्ष पद पर दो बार नहीं रह सकेगा। वहीं, मंत्री मंडल के कार्यकाल को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

बैठक में अध्यक्ष भगवान व्यास, उपाध्यक्ष रामदेव नागला एवं जगदीश तिवारी, मंत्री श्यामसुंदर तिवारी, कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल ओझा, उपमंत्री नरसिंह जोशी, संपत व्यास, कार्यकारिणी सदस्य रामदेव उपाध्याय, गजानंद तिवारी, रामदेव तिवारी, भगवान तिवारी, घनश्याम व्यास, दीपक, सदीप जायलवाल, लालचंद जोशी, राजेश उपाध्याय, शाम ओझा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

अंत में मंत्री श्यामसुंदर तिवारी ने सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही बैठक का समापन हुआ।

मानव सेवा ही माधव सेवा : सुशील गुप्ता



हैदराबाद। राधे-राधे ग्रुप हैदराबाद के तत्वावधान में नामपल्ली स्थित पब्लिक गार्डन पिलर नंबर 1265-ए के पास गुरुवार को नियमित सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जरूरतमंदों को अन्न सेवा प्रदान की गई। कार्यक्रम में ग्रुप के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए सेवा और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाया।

इस अवसर पर सुशील गुप्ता ने अपने

विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा के संकल्प को लेकर राधे-राधे ग्रुप हैदराबाद निरंतर सेवा कार्यों में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति की आवश्यकता के समय उसके साथ खड़ा होना और उसे भोजन उपलब्ध कराना मानवता की सच्ची सेवा है। सेवा कार्य में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक जरूरतमंद को समान भाव से सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि

राधे-राधे ग्रुप द्वारा नियमित रूप से किए जा रहे सेवा कार्यों के पीछे निस्वार्थ सेवा की भावना है। अन्न सेवा के माध्यम से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने के साथ ही समाज में सेवा, संस्कार और सहयोग का संदेश भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सेवा कार्य बिना किसी दिखावे और स्वाधे के किया जाता है, तो वह समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है।

राधे-राधे ग्रुप के सदस्य सेवा को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं मानते, बल्कि इसे निरंतर चलने वाला सामाजिक दायित्व मानकर कार्य कर रहे हैं। नियमित सेवा कार्यक्रमों में सदस्यों की सहभागिता यह संदेश देती है कि समाज के सक्षम लोगों को आगे आकर जरूरतमंदों की सहायता के लिए अपना योगदान देना चाहिए।

कार्यक्रम में राम प्रकाश अग्रवाल, सुशील गुप्ता, शीतल गुप्ता, संजय गोयल, किरण गोयल, भाकर राम कुमावत, जय प्रकाश सारड़ा, कैलाश केडिया, निर्मला केडिया, प्रीतिका अग्रवाल, भगत राम गोयल, मनीष चिंडालिया तथा जगन गुप्ता सहित राधे-राधे ग्रुप के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने सेवा कार्य में सहयोग करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया।

ईसीआईएल ने सीएसआर के तहत राजकीय सामान्य अस्पताल कोटागुडेम को 67.41 लाख के चिकित्सा उपकरण सौंपे

हैदराबाद, 18 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत राजकीय सामान्य अस्पताल, कोटागुडेम को 67.41 लाख रुपये मूल्य के आधुनिक चिकित्सा उपकरण सौंपे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और आम जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल की पहुंच में सुधार करना है। चिकित्सा उपकरणों को औपचारिक रूप से कोटागुडेम के जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट श्री अंकित (आईएसएस), ईसीआईएल के निदेशक (कार्मिक) श्री कन्नन वी. ए. एस. और जीजीएच कोटागुडेम के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राधा मोहन की गरिमामयी उपस्थिति में अस्पताल को सौंपा गया।

इस अवसर पर ईसीआईएल के निदेशक (कार्मिक) श्री कन्नन वी. ए. एस. ने कहा कि चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की यह पहल लोगों को समय पर अपातकालीन सेवाएं प्राप्त करने में मदद करेगी, जिससे



कीमती जानें बचाई जा सकेंगी। उन्होंने दो-हराया कि ईसीआईएल अपने सीएसआर पहलों के माध्यम से समाज के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है और समुदाय के कल्याण के लिए ऐसे प्रयास जारी रखेगा।

कोटागुडेम के जिला कलेक्टर श्री अंकित (आईएसएस) ने राजकीय सामान्य अस्पताल को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए ईसीआईएल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सार्वजनिक कल्याण के प्रति ईसीआईएल की

प्रतिबद्धता की सराहना की और जिले के सर्वांगीण विकास के लिए और अधिक सीएसआर पहल करने का अनुरोध किया।

समारोह के दौरान ईसीआईएल के डॉ. पी. वेणु बाबू (मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी-सीएसआर), श्री सुनील कुमार जे., श्री अनिल कुमार, श्री पूर्णचंद्र पी. (अध्यक्ष, ईसीओए) और श्री सांभूमूर्ति भी उपस्थित रहे, जिनके सहयोग से इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

79वें हैदराबाद मुक्ति दिवस पर वीरुला सैनिक स्मारक में उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि



हैदराबाद, 18 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो): 79वें हैदराबाद मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सिकंदराबाद स्थित फेड ग्राउंड्स में 'वीरुला सैनिक स्मारक' (वीर सैनिक स्मारक) पर पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीदों को भावभीनी

श्रद्धांजलि दी गई। इस गरिमामयी कार्यक्रम में देश और प्रदेश के कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से: श्री शिव प्रताप शुक्ल (राज्यपाल, तेलंगाना), श्री गजेंद्र सिंह शेखावत (केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री), श्री जी. किशन रेड्डी (केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री), श्री बंडी संजय कुमार (केंद्रीय गृह राज्य मंत्री)। इस अवसर पर राष्ट्रीय

सैनिक संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष तथा सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक डॉ. योगेश राज श्रीवास्तव भी पूर्व सैनिकों के साथ उपस्थित रहे और शहीदों को नमन किया। पुष्पांजलि के पश्चात स्मारक के निकट गणमान्य अतिथियों एवं पूर्व सैनिकों का एक स्मृति चित्र भी लिया गया।

एमबीआई ग्रेटर हैदराबाद ने हर्षोल्लास से मनाई गणेश चतुर्थी



हैदराबाद, 17 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। एमबीआई ग्रेटर हैदराबाद की ओर से गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम क्लब की सचिव रश्मि गुप्ता के निवास स्थान पर हर्षोल्लास एवं भक्तिभाव के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत क्लब की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी सेवा कार्यों एवं गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई।

भगवान गणेश के आगमन के साथ ही वातावरण भक्तिमय हो गया। सभी सदस्यों ने भजनों का आनंद लिया। इसके बाद तंबोला खेल का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का समापन भगवान गणेश की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष दिव्या गुप्ता, कोषाध्यक्ष कविता गुप्ता तथा कार्यकारिणी सदस्य पूजा गुप्ता, भारती गुप्ता, रेनु गुप्ता, आरती गुप्ता, प्राची गुप्ता, शालिनी गुप्ता, अंजली गुप्ता सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहें।



हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर गांधी भवन में सुबह 10.30 बजे ध्वजारोहण किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष टी. कुमार राव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर सांसद मल्लू रवि, सेवादल अध्यक्ष जितेंद्र, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एन.के. सिंह सहित कांग्रेस के अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।



हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर लोअर धूलपेट में झंडा वंदन करते हुए पूर्व पार्षद लाल सिंह। साथ में हैं जयपाल सिंह, कैलाश सिंह, संजीवराज सिंह, के. लालसिंह, एम. अशोक सिंह, एम. किशन, प्रदीप सिंह एवं अन्य।

कीसरा थाने में 5 लाख की कथित रिश्त का ट्रैप

बेल के नाम पर 10 लाख की मांग का आरोप, 5 लाख लेते एसआई - सीआई एसीबी के जाल में फंसे !

हैदराबाद, 17 सितम्बर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

शहर में सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है, लेकिन कानून की रक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली खाकी पर ही रिश्त-तखोरी के आरोप लगाना गंभीर सवाल खड़े करता है। कीसरा थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए सब-इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र रेड्डी को 5 लाख की कथित रिश्त लेते हुए ट्रैप किया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक आरोपी को स्टेशन बेल दिलाने के मामले में कीसरा थाना इंस्पेक्टर ए. अंजनेयुलु और एसआई ज्ञानेंद्र रेड्डी द्वारा शिकायतकर्ता से कथित तौर पर रिश्त की मांग की गई थी। आरोप है कि पहले 10 लाख की मांग की गई और बाद में 5 लाख



में सोदा तय हुआ। तय रकम एसआई ज्ञानेंद्र रेड्डी को दिए जाने की बात सामने आई। शिकायत के आधार पर एसीबी ने जाल बिछाया। बताया गया कि गणेश विसर्जन ड्यूटी के दौरान कीसरा झील के पास एसआई ज्ञानेंद्र रेड्डी ने कार में कथित तौर पर 5 लाख की रिश्त

राशि स्वीकार की। इसी दौरान एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया। सूत्रों के अनुसार, एसीबी अधिकारियों को देखकर एसआई ने कथित तौर पर मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने उन्हें पकड़ लिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों

से पुलिस अधिकारियों द्वारा उससे बिरयानी और कूल ड्रिंक्स की मांग की जा रही थी। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है।

ट्रैप के बाद एसीबी की टीमों ने कीसरा पुलिस स्टेशन के साथ संबंधित अधिकारियों के आवासों पर भी तलाशी ली। कार्रवाई एसीबी डीएसपी मजीद अली खान की निगरानी में किए जाने की जानकारी है।

खाकी पर लगे इन आरोपों के बीच एसीबी की कार्रवाई ने पुलिस विभाग में हलचल पैदा कर दी है। हालांकि, रिश्त की मांग, रकम के लेन-देन और अन्य आरोपों से जुड़े अंतिम तथ्य जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। मामले में आगे की कार्रवाई और जांच जारी है।

अग्रवाल समाज तेलंगाना की विभिन्न समितियों के चेयरमैन मनोनीत

हैदराबाद, 17 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। अग्रवाल समाज तेलंगाना के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयल द्वारा समाज की विभिन्न समितियों के चेयरमैन एवं संयोजकों का मनोनयन किया गया है। समाज के मीडिया एवं प्रचार-प्रसार चेयरमैन मुकुंद लाल अग्रवाल ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दंपति सम्मेलन समिति के चेयरमैन सुरेश कुमार अग्रवाल (दिल्लीवाले) तथा संयोजक राजेंद्र कुमार अग्रवाल को मनोनीत किया गया है। प्रतिमाह राशन किट वितरण एवं एकल नारी पेंशन योजना समिति के चेयरमैन चिमन लाल सुरेश कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। दीपावली मिलन एवं अन्नकूट प्रसाद समिति के चेयरमैन राजेंद्र कुमार अग्रवाल तथा समाज की सदस्यता अभियान समिति के चेयरमैन मुकुंद लाल अग्रवाल को मनोनीत किया गया है।

सदस्यता अभियान को गति देने पर जोर सदस्यता अभियान समिति के चेयरमैन मुकुंद लाल अग्रवाल ने बताया कि उनकी एवं उनकी टीम का प्रयास रहेगा कि सभी अग्रबंधु समाज की सदस्यता ग्रहण कर समाज से जुड़ें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अग्रवाल समाज द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें इंडक्शन चूल्हा वितरण,



एकल नारी पेंशन, विद्यार्थियों को शिक्षा सहायता, श्री जगन्नाथपुरी धाम की धार्मिक यात्रा, श्रीशैलम तीर्थ की धार्मिक यात्रा तथा राशन किट वितरण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त योजनाओं के लाभार्थी अपने परिवार के सभी सदस्यों को समाज का सदस्य बनाकर उनके नाम से प्रिविलेज कार्ड बनवाएं। जिन परिवारों के सभी सदस्य समाज के सदस्य होंगे, उन्हें आगामी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा।

नवरात्रि में नौ दिन डांडिया कार्यक्रम आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि नवरात्रि के अवसर पर 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक नौ दिवसीय डांडिया कार्यक्रम क्लासिक-3 कन्वेंशन, शमशाबाद में आयोजित किया जाएगा। इसमें सिनेमा जगत के कई विख्यात कलाकारों के भाग लेने की संभावना है। इसके अलावा

अहमदाबाद एवं सूरत के डांडिया और गरबा कलाकार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

1 अक्टूबर को दंपति सम्मेलन दंपति सम्मेलन का आयोजन 1 अक्टूबर को होटल ताज कृष्ण, बंजारा हिल्स में किया जाएगा। सम्मेलन के चेयरमैन सुरेश कुमार अग्रवाल (दिल्लीवाले) तथा संयोजक राजेंद्र कुमार अग्रवाल रहेंगे।

महाराजा अग्रसेनजी की जयंती का आयोजन 11 अक्टूबर को क्लासिक-3 कन्वेंशन में किया जाएगा। वहीं, दीपावली मिलन एवं अन्नकूट प्रसाद कार्यक्रम 15 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के चेयरमैन राजेंद्र कुमार अग्रवाल हैं। समाज की ओर से बताया गया कि उपरोक्त सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संबंधित चेयरमैन एवं संयोजकों से संपर्क किया जा सकता है।

चेवेल्ला के सरकारी खजाना कार्यालय में रिश्त का जाल, एसीबी विभाग ने रंगे-हाथ दबोचा



2.50 लाख रुपये की कथित रिश्त मांगने का आरोप

1 लाख रुपये की पहली किश्त लेते एसीबी की कार्रवाई

दो अधिकारी और एक निजी व्यक्ति एसीबी के शिकंजे में

वेतन-पेंशन से जुड़े लाखों रुपये के भुगतान का मामला

चेवेल्ला, 17 सितम्बर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला स्थित सरकारी खजाना कार्यालय (डिविजनल सब-ट्रेजरी) में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई से सरकारी कार्यालयों में कथित रिश्तखोरी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। गुरुवार को एसीबी रंगारेड्डी रेंज यूनिट ने कार्रवाई

करते हुए सब-ट्रेजरी अधिकारी मदिगा लक्ष्मैया, सहायक ट्रेजरी अधिकारी कवाली अनुराधा और निजी व्यक्ति वंडे जंगैया उर्फ चिन्ना को रिश्त के मामले में आरोपी बनाया। एसीबी के प्रेस नोट के अनुसार, शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 2.50 लाख रुपये की रिश्त मांगी गई थी। पहली किश्त के रूप में 1 लाख रुपये स्वीकार किए जाने के दौरान एसीबी ने कार्रवाई की। आरोप है कि सब-ट्रेजरी अधिकारी लक्ष्मैया ने अपने हिस्से के 50 हजार रुपये स्वीकार किए, जबकि सहायक ट्रेजरी अधिकारी अनुराधा के निर्देश पर निजी व्यक्ति जंगैया ने कथित तौर पर 50 हजार रुपये लिए।

मामला महज कुछ हजार रुपये के भुगतान का नहीं, बल्कि लाखों रुपये से जुड़े सरकारी वित्तीय कार्य का बताया गया है। एसीबी के मुताबिक, शिकायतकर्ता के निलंबन अवधि के 23,25,390 रुपये के वेतन बिलों को प्रोसेस कर आगे भेजने तथा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन समायोजन के 4,29,000 रुपये के बकाया भुगतान से संबंधित सरकारी कार्य करने के बदले कथित रूप से 2.50 लाख रुपये की मांग की गई थी।

पीएम मोदी के जन्मदिन पर 'मोदी वाणी' का लोकार्पण



हैदराबाद, 17 सितंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर त्रिभाषी ग्रंथ 'मोदी वाणी' सेवा संकल्प विकासित भारत' का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी, पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और भाजपा तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने संयुक्त रूप से गुरुवार सुबह नामपल्ली स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में ग्रंथ का लोकार्पण किया। तेलंगाना राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं राजनीतिक-सामाजिक विश्लेषक डॉ. वंकुलाभराम कृष्ण मोहन राव ने इस ग्रंथ को तैयार किया है।

प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के बारह वर्षों के कार्यकाल के दौरान देश-विदेश में दिए गए भाषणों का व्यापक अध्ययन कर उनके प्रमुख विचारों, वक्तव्यों और उद्धरणों को इस ग्रंथ में संकलित किया गया है। पुस्तक में मोदी के विचारों, शासन-दृष्टि और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को समग्र रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसे उनके 76वें जन्मदिन के अवसर पर विशेष भेंट के रूप में प्रकाशित किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से चुने गए

प्रामाणिक उद्धरणों का त्रिभाषी संकलन।

प्रत्येक उद्धरण को सर्वप्रथम मोदी द्वारा कहे गए मूल हिंदी स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद उसका सहज एवं भावपूर्ण तेलुगु तथा अंग्रेजी रूप दिया गया है।

'उद्धरणों का चयन प्रधानमंत्री के आधिकारिक भाषणों और विश्वसनीय प्रमाणिक स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर किया गया है।' प्रत्येक उद्धरण के साथ उसका संदर्भ, भाषण की पृष्ठभूमि और मूल स्रोत का विवरण दिया गया है। 'सेवा, संकल्प, सुशासन, अंत्योदय, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण, युवा शक्ति, किसान कल्याण, आत्मनिर्भर भारत, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण तथा विश्व मंच पर भारत के नेतृत्व जैसे व्यापक विषयों को पुस्तक में स्थान दिया गया है।

मोदी के संदेशों, शासन-दर्शन और राष्ट्र के भविष्य के प्रति उनकी दृष्टि को तीन भाषाओं के पाठकों तक पहुंचाने का यह प्रयास किया गया है। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य मल्ला कोमुरैया, भाजपा के राष्ट्रीय नेता पोंगुलेटी सुधाकर रेड्डी, प्रदेश उपाध्यक्ष शांतकुमार, जयश्री, कल्याण नायक, प्रदेश महामंत्री डॉ. एन. गौतम राव, डॉ. वेमुला अशोक, टी. वीरेंद्र गौड़, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गणेश, वरिष्ठ नेता श्रीनी रेड्डी, गोपाल, सुभाष चंद्र, रानी रुद्रमा और पद्म सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों, पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।



त्रिशूल और डमरू के साथ, गणपति बाप्पा की शरण में भाजपा नेता सपना गुप्ता।

फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेंट में धूमधाम से मनाया गया तेलंगाना प्रजा पालना दिनोत्सवम

फ्यूचर सिटी/इब्राहिमपटनम।, 17 सितम्बर (शुभ लाभ ब्यूरो)। फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेंट मुख्यालय, इब्राहिमपटनम में गुरुवार को 'तेलंगाना प्रजा पालना दिनोत्सवम' का आयोजन पूरी गरिमा और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर आयोजित औपचारिक समारोह में कमिश्नरेंट के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान



फ्यूचर सिटी के पुलिस आयुक्त डॉ. तरुण जोशी (आईपीएस) ने ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात पुलिस टुकड़ी द्वारा प्रस्तुत गॉर्ड ऑफ ऑनर स्वीकार करते हुए उन्होंने पेरंडा का निरीक्षण किया।

इस अवसर पर फ्यूचर सिटी की संयुक्त पुलिस आयुक्त श्रीमती जी. चंदना दीप्ति (आईपीएस) और महेश्वरम ज़ोन के पुलिस उपायुक्त श्री के. नारायण रेड्डी

(आईपीएस) विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह में कमिश्नरेंट के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी सहभागिता की।

यह आयोजन अनुशासित पुलिसिंग, जनसेवा और उत्कृष्ट संस्थागत मूल्यों के प्रति फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेंट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संपूर्ण कार्यक्रम देशभक्ति और सेवा भावना के माहौल में संपन्न हुआ।



उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, भाजपा राज्य सचिव तथा अलाई बलाई फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती बंडारू विजयलक्ष्मी ने बेगमपेट में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर तेलंगाना के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला भी शामिल हुए। इस अवसर पर सी.पी. राधाकृष्णन के साथ बंडारू दत्तात्रेय ने विभिन्न विषयों पर आत्मीय रूप से चर्चा की।